घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 211- मंगलवार 02 - जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत-म्यांमार के बीच सुरक्षा आर्थिक सहयोग,संपर्क सुविधाओं के विस्तार पर बनी सहमति...

नई दिल्ली,01 जून 2026। भारत और म्यांमार ने आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग तथा संपर्क सुविधाओं के विस्तार पर सहमति व्यक्त की है। आधारभूत परियोजनाओं को लागू करने तथा व्यापार एवं द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही पड़ोसी देश की ओर से आश्वासन दिया गया है कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ उसकी भूमि का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के बीच सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। चर्चा में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग,सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों देशों ने स्वास्थ्य,शिक्षा,ऊर्जा,कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति ह्लाइंग 30 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अप्रैल 2026 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। मूल रूप से उन्हें 'इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' शिखर सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन सम्मेलन स्थगित होने के बाद इस अवसर का उपयोग द्विपक्षीय वार्ता के लिए किया गया। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इसमें पांच कैबिनेट मंत्री, तीन उपमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ 6 जून को प्रदर्शन का किया ऐलान...

नई दिल्ली,01 जून 2026। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नाम से सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले अभिजीत दीपके ने 6 जून को भारत लौटकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अमेरिका के बोस्टन में रह रहे महाराष्ट्र निवासी अभिजीत दीपके ने सोमवार को 'काकरोच इज बैक' नामक एक्स अकाउंट पर साझा वीडियो में कहा कि वह शनिवार,6 जून की सुबह भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया है। प्रश्नपत्र लीक के कारण नीट के छात्रों की आत्महत्या और लाखों बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दीपके ने दावा किया कि इस मुद्दे पर उनकी याचिका पर 8 लाख छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं और देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि नीट के 22 लाख अभ्यर्थी, सीबीएसई के 17 लाख छात्र, सीयूईटी के 16 लाख छात्र और एसएससी जीडी के 16 लाख छात्र कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। दीपके ने समर्थकों से अपील की कि वे 6 जून को दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करें और मिलकर संसद मार्ग थाने से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगें। सीजेपी संस्थापक ने कहा कि अब समय आ गया है कि छात्र संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा संबंधी विवादों और व्यवधानों ने छात्रों को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया है।

पेपर लीक से ध्वस्त हो रही शिक्षा व्यवस्था युवाओं का भविष्य संकट में : पवन खेड़ा

नई दिल्ली,01 जून 2026। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि देश में लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं,जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और कई छात्र मानसिक दबाव में आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और कई परीक्षाओं में अनियमितताओं के चलते युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने एनईईटी,सीयूईटी,जेईई मेन और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सीबीएसई परीक्षा मूल्यांकन और स्कैनिंग प्रणाली में बदलाव के दौरान टेंडर प्रक्रिया में नियमों में संशोधन किया गया, जिससे एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि पहले के टेंडर में टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं, लेकिन बाद में शर्तों में बदलाव कर नए टेंडर में अलग कंपनी को अवसर मिला। खेड़ा ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और स्कैनिंग प्रक्रिया में बदलाव के कारण पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकारी खर्च में गिरावट आई है और इसे लेकर युवाओं के भविष्य पर संकट खड़ा हो रहा है। जहां देश के युवा परीक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं सार्वजनिक संदेशों में अलग विषयों पर चर्चा की जा रही है।

अभिषेक पर हमला साजिश,दिल्ली तक होगा आंदोलन : ममता बनर्जी

कोलकाता,01 जून 2026। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने और पार्टी नेताओं को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले कोई सामान्य घटनाएं नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे सुनियोजित साजिश थी। ममता ने चेतावनी दी कि यदि कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो वह आंदोलन को दिल्ली तक ले जाएंगी।पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को जान से मारने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार हमले कर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है,लेकिन उनकी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है।

पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का विस्तार

राज्यपाल ने 35 नए मंत्रियों को दिलाई शपथ

अर्जुन सिंह,तपस रॉय मंत्री बने,शुभेंदु मंत्रिमंडल में अब 41 मिनिस्टर

कोलकाता,01 जून 2026। सोमवार को पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। कोलकाता के लोक भवन में राज्यपाल आरएन रवि ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी उपस्थित रहे। सोमवार को 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 19 राज्य मंत्री और 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों में दीपक बर्मन,तपस रॉय,शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव,अर्जुन सिंह,गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता,जगन्नाथ चट्टोपाध्याय,कल्याण चक्रवर्ती,अजय पोद्दार,शरद्वत मुखर्जी,दूध कुमार मंडल और अनुप कुमार दास शामिल हैं। राज्य मंत्रियों में जोएल मुर्मू,हरेकृष्ण बेरा,आनंदमय बर्मन, अशोक डिंडा, नदियार चंद बाउरी, विशाल लामा,शांतनु प्रमाणिक, मौमिता बिस्वास मिश्रा, उमेश रे,पूर्णिमा चक्रवर्ती,कौशिक चौधरी, भास्कर भट्टाचार्य,दिबाकर घरामी,अमिया किस्कू, कलिता माझी,गार्गी दास घोष,बिराज विश्वास, दीपंकर जना और सुमना सरकार को जगह मिली है। इसके अलावा, इंद्रनील खान,मालती राभा रॉय और राजेश महतो ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली। 35 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। 9 मई को पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने के साथ छह मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अलावा अग्निमित्रा पॉल,दिलीप घोष,निसिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू शामिल थे। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर 35 नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया था। संभावना है कि नए मंत्रियों के विभागों (पोर्टफोलियो) की घोषणा भी आज ही की जाएगी।

गौरतलब है कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। बाद में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा की जीत के बाद पार्टी की कुल सीटें बढ़कर 208 हो गई।

सीबीएसई छात्रों की जेब काटे,इसलिए टेंडर प्रक्रिया में ढील दी : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 01 जून 2026। सीबीएसई 12वीं की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली (ओएसएम) पर उपजा विवाद अब एक बड़े राजनीतिक और तकनीकी घोटाले का रूप ले चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि एक छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका का सही मूल्यांकन कराने के लिए करीब 2 हजार रुपए खर्च करना पड़ते हैं। ऐसे में इस साल करीब साढ़े 18 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। अंदाजा लगाईऐ लाखों छात्रों ने कितना पैसा खर्च किया होगा। राहुल गांधी का आरोप है कि इसके पीछे टेंडर प्रक्रिया में ढील दी गई ताकि इस मोटी रकम का सीधा फायदा एक कंपनी को मिल सके। उन्होंने कहा कि सीबीएसई अब छात्रों की जेब कतर रहा है। उनका दावा है कि निविदा (टेंडर) प्रक्रिया में जानबूझकर ढील देकर एक खास निजी वेंडर, सीओईएमपीटी एजू टेक को फायदा पहुंचाया गया,जिसके कारण 18.5 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। राहुल गांधी के अनुसार, मई 2025 के शुरुआती टेंडर में उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखते हुए ऑटोमैटिक रोबोटिक स्कैनर और 300 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन से स्कैन करने की अनिवार्य शर्त थी। लेकिन अगस्त के संशोधित टेंडर में इन शर्तों को हटाकर रिज़ॉल्यूशन को 200 डीपीआई कर दिया गया। आरोप है कि इसके बाद वेंडर ने कॉपियों को पेशेवर स्कैनर के बजाय सामान्य मोबाइल फोन से स्कैन किया। इसके प्रमाण के रूप में छात्रों की कॉपियों पर ड्रॉप शैडो (परछाई) और मोड़ने के निशान साफ देखे गए हैं, जो केवल मोबाइल से फोटो खींचने पर आते हैं। इस तकनीकी लापरवाही के कारण मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी सामने आई है। सोशल मीडिया पर धुंधली कॉपियों, गायब पन्नों और बिना जांचे गए जवाबों के स्क्रीनशॉट की बाढ़ आ गई है। कई छात्रों को दूसरों की उत्तर पुस्तिकाएं आवंटित होने की भी शिकायतें मिली हैं।

सूर्या चौहान हत्याकांड पर सीएम योगी का सख्त संदेश,बोले...कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे

बिजनौर,01 जून 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के अफजलगढ़ में आयोजित एक जनसभा के दौरान सूर्या चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि दोस्ती के नाम पर धोखा और हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ खड़ी है और जो लोग सामाजिक सौहार्द तथा कानून-व्यवस्था को चुनौती देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्या चौहान को दोस्ती के नाम पर विश्वासघात का सामना करना पड़ा और घटना के बाद पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' साथ ही उन्होंने परिवारों से अपने बच्चों को सही संस्कार देने की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, तो यह उसकी बड़ी जिम्मेदारी और चूक है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों और पट्टाधारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी वितरित करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से आए 1645 परिवारों और कई पूर्व सैनिकों को भूमिधरी अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे इन परिवारों को अब उनकी जमीनों का वैध मालिकाना हक मिला है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के नए रास्ते खोजने के मुद्दे पर हुई चर्चा...

रक्षा मंत्री राजनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की

नई दिल्ली,01 जून 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में अपने समकक्ष और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ इंडिया-ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग की सह-अध्यक्षता की। इस डायलॉग में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति का आकलन करने के साथ ही आपसी सहयोग के नए रास्ते खोजने के मुद्दे पर चर्चा की गई। भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आपकी सरकार को हाल ही में जारी की गई 2026 की 'राष्ट्रीय रक्षा रणनीति' और 'एकीकृत निवेश कार्यक्रम' के लिए बधाई देना चाहूंगा। आज की चर्चा के दौरान मैं इस नीति दस्तावेज पर और भारत-ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंधों में विकास की संभावनाओं पर आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा कि हमने मिलकर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की और इसे और अधिक बढ़ाने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद से पहले नई दिल्ली पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मार्लेस का स्वागत किया। बाद में रिचर्ड मार्लेस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तीनों सेनाओं की ओर से 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में 'डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग' में रक्षा सहयोग की समीक्षा करने के साथ ही भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश की गई। रिचर्ड मार्लेस का यह दौरा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हुई पहली 'डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग' के बाद हो रहा है और यह इंडिया-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती रफ्तार को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत के खुले, सबको साथ लेकर चलने वाले और खुशहाल इंडो-पैसिफिक के विजन में एक अहम साझेदार है। यह दौरा भारत-ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप की बढ़ती मजबूती को भी प्रदर्शित करता है।

तृणमूल कांग्रेस ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाला...

कोलकाता,01 जून 2026। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने दो विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। इन विधायकों के नाम संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी हैं। तृणमूल ने दोनों पर पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, निष्कासन की जानकारी दोनों नेताओं को ईमेल और व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचित कर दी गई है। साथ ही इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु को भी जानकारी दे दी गई है। सोमवार को अलग-अलग जारी निष्कासन नोटिस में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि दोनों विधायक पार्टी के अधिकृत नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में बार-बार अनुपस्थित रहे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। नोटिस में आगे कहा गया है कि यह भी देखा गया है कि दोनों विधायकों ने ऐसी गतिविधियों में भाग लिया है और ऐसे बयान दिए हैं जो पार्टी के हितों के लिए हानिकारक हैं। इस मामले पर उचित विचार-विमर्श के बाद दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। निष्कासन के बाद संदीपन साहा ने पार्टी के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, पार्टी उनका समर्थन करती है, जबकि नैतिक कदम उठाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपस्थिति रजिस्टर में किए गए हस्ताक्षर को किसी प्रस्ताव पर समर्थन के हस्ताक्षर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस घटनाक्रम से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा था कि संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने ही विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके हस्ताक्षरों की जालसाजी की गई है।मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस मंत्री के रूप में मामला उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जांच में सीआईडी को शामिल करने का निर्देश दिया था। यह पूरा मामला विधानसभा में विपक्ष के नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक की नियुक्ति से जुड़े कथित हस्ताक्षर विवाद से संबंधित है।

त्विशा शर्मा मर्डर मिस्ट्री...

सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा एफआईआर के बाद 3 दिन तक भोपाल में छिपा था आरोपी समर्थ

भोपाल,01 जून 2026। हाई प्रोफाइल त्विशा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। जांच में आरोपी समर्थ की फरारी को लेकर बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी तफ्तीश का दायरा और बढ़ा दिया है। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ है कि बीते 15 मई को मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी समर्थ तत्काल शहर छोड़कर नहीं भाग पाया था। वह करीब तीन दिनों तक भोपाल में ही छुपा रहा। इसके बाद वह जबलपुर पहुंचा, जहां उसने लगभग पांच दिनों तक फरारी काटी। अब सीबीआई इस पूरी अवधि के दौरान समर्थ के संपर्कों, उसकी गतिविधियों और फरारी काटने में उसे मिली संभावित मदद (शेल्टर देने वालों) की विस्तृत पड़ताल कर रही है।

देश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार : केंद्र सरकार

नई दिल्ली,01 जून 2026। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद हम कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति को बनाए रखने में सफल रहे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में दावा करते हुए कहा कि हमारे पास पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री असामान्य रूप से ज्यादा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में एलपीजी से संबंधित 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं,जबकि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का अनुरोध किया गया है। तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने भी 460 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर अचानक निरीक्षण किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 42 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों पर जुर्माना लगाया गया है। शर्मा ने कहा कि मार्च से अब तक लगभग 8,56,000 पीएनजी कनेक्शनों को गैस से जोड़ा गया है, 2,96,000 कनेक्शन के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है और 8,78,000 नए ग्राहक पंजीकृत किए गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग की अतिरिक्त

भारत में 'दिव्यास्त्र' ड्रोन बनाने का रास्ता साफ...दिव्यास्त्र मार्क-1 का भरोसेमंद प्रदर्शन

जोधपुर में 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रेगिस्तानी तापमान में मोबाइल लॉन्चर से किया गया परीक्षण

नई दिल्ली,01 जून 2026। अब भारत में 'दिव्यास्त्र' ड्रोन बनाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूरतों को देखते हुए लॉन्ग रेंज ड्रोन विकसित करने की कोशिशों में भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत के स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी होवरइट ने दिव्यास्त्र मार्क-1 विकसित करके सफल परीक्षण भी कर लिया है। राजस्थान के जोधपुर में 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रेगिस्तानी तापमान और तेज हवाओं में टेस्ट किए जाने पर इस प्लेटफ़ॉर्म ने मुश्किल फील्ड स्थितियों में भी भरोसेमंद प्रदर्शन दिखाया। कंपनी के अनुसार दिव्यास्त्र मार्क-1 ने अपने ऑपरेशनल प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरे किए, जिसमें वाहन पर लगे मोबाइल लॉन्चर से कई लॉन्च, लाइव आईएसआर मिशन और टर्मिनल अटैक प्रोफाइल शामिल थे। इस प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर दिव्यास्त्र मार्क-1 यूएवी को एक वाहन पर लगे मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इससे प्लेटफॉर्म की तेजी से तैनात होने की क्षमता, युद्ध के मैदान में गतिशीलता और जमीनी हालात में टैक्टिकल लॉन्च की तैयारी का प्रदर्शन हुआ। इस अभ्यास ने ऑपरेशनल माहौल में गतिशील आईएसआर और टोही मिशनों में मदद करने की यूएवी की क्षमता को भी और पुख्ता किया। दिव्यास्त्र मार्क-1 स्वदेशी टैक्टिकल यूएवी है, जिसे खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही और सटीक हमले के मिशनों के लिए विकसित किया गया है। 500 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज और 5 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ इस प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक निगरानी, लक्ष्य की पहचान और टैक्टिकल कार्रवाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस यूएवी को पेलोड, संचार रिले सिस्टम और मिशन-विशिष्ट वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे यह अलग-अलग तरह के मिशनों में ऑपरेशनल किया जा सकता है। 'दिव्यास्त्र' नाम से भारत में दो प्रमुख और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां विकसित की गई हैं। एक मिशन दिव्यास्त्र (मिसाइल) है और दूसरी दिव्यास्त्र मार्क-1' लड़ाकू ड्रोन-लोइटरिंग म्यूनिशन है। इसे भारत में ही डिजाइन, विकसित और इंटीग्रेट किया गया है। यह एक स्वदेशी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 'लोइटरिंग म्यूनिशन' प्रणाली है। यह प्रणाली भारतीय सेना के लिए रक्षा तैयारियों में एक बड़ा गेम-चेंजर मानी जा रही है। इसे लंबी दूरी की सटीक निगरानी, सामरिक हमलों और दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 'एआई और स्वार्म' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

संपादकीय

बंगाल में हिंसा

पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के तत्काल बाद जो हिंसा हुई थी और जिसमें भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर हमले किए थे,वह करीब-करीब थम गई थी,लेकिन पिछले दिनों जिस तरह टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और गत दिवस इसी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी भी भीड़ के आक्रोश एवं पथराव का शिकार हुए,वह कोई शुभ संकेत नहीं। इस सिलसिले को रोका ही जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ गुस्साई भीड़ ने जो धक्कामुक्की एवं मारपीट की,उसे तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है,लेकिन हालिया चुनाव के बाद जो हिंसा देखने को मिली, उसकी तुलना उस भीषण अराजकता से नहीं की जा सकती,जो पिछले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद देखने को मिली थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं-नेताओं और उनके समर्थकों ने विरोधी दलों और विशेष रूप से भाजपा के उन लोगों पर कहर बरपाया था, जिनके बारे में उन्हें शक था कि उन्होंने ममता की पार्टी को वोट नहीं दिया। वह अराजकता इतनी भयावह एवं आतंकित करने वाली थी कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए असम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। यदि तब ममता बनर्जी ने उस हिंसा को गंभीरता से लिया होता और उस पर रोक लगाने की कोशिश की होती तो शायद आज जो कुछ देखने को मिल रहा है, वह नहीं दिखता। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ममता बनर्जी ने अपने शासन में कानून एवं व्यवस्था को कलंकित करने वाली उस हिंसा से पल्ला झाड़ लिया था। उन्होने ऐसा ही उसके बाद की राजनीतिक हिंसा के मामले में भी किया।

बंगाल के बारे में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यहां राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा का एक लंबा दौर रहा है। एक तरह से राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बन गई है। भाजपा को प्राथमिकता के आधार पर हिंसा की इस संस्कृति को खत्म करना होगा। उसे ऐसा इसके बावजूद करना होगा कि इस बार हिंसा का वैसा भयावह रूप देखने को नहीं मिला है। भाजपा सरकार को न केवल पुलिस-प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने होंगे, बल्कि अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह संदेश देना होगा कि किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बंगाल में हर स्तर पर वास्तविक सुधार के लिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि कानून एवं व्यवस्था को ठीक करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इससे ही राज्य सही तरह से पटरी पर आएगा। कोई भी राज्य सही तरह से तभी आगे बढ़ता है,जब वहां कानून एवं व्यवस्था नियंत्रित होती है।

क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोरा बुलबुला है या वास्तविक चुनौती?

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। कृषि क्रांति ने मनुष्य को स्थायित्व दिया, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और श्रम की परिभाषा बदली,सूचना क्रांति ने ज्ञान और संचार की सीमाएं समाप्त कर दीं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की क्रांति मानव इतिहास के एक नए मो पर खड़ी है। यह केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है,बल्कि मनुष्य की बुद्धि, निर्णय क्षमता,रोजगार, सामाजिक संरचना, शासन व्यवस्था और यहां तक कि उसके अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। यही कारण है कि आज विश्वभर में यह बहस तेज हो रही है कि क्या एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगी या वह धीरे-धीरे मनुष्य के महत्व को ही चुनौती देने लगेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मशीनों को चलाने तक सीमित नहीं है,बल्कि वह उन कार्यों को भी करने लगी है जिन्हें लंबे समय तक केवल मनुष्य की विशिष्ट क्षमता माना जाता था। लेखन, चित्र निर्माण, संगीत रचना, रोगों का निदान, न्यायिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णय जैसे क्षेत्रों में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने अनेक नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि मशीनें सोचने, सीखने और निर्णय लेने लगेंगी तो मनुष्य की विशिष्टता क्या रह जाएगी? यह प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दार्शनिक और नैतिक भी है।

मानव अस्मिता का आधार उसकी चेतना,संवेदना,रचनात्मकता और नैतिक विवेक है। एआई के पास विशाल सूचनाओं का भंडार और तीव्र गणनात्मक क्षमता अवश्य है,लेकिन उसके पास अनुभवजन्य चेतना, करुणा, आत्मबोध और मूल्यबोध नहीं है। फिर भी जब मशीनें कविता लिखती हैं, चित्र बनाती हैं और संवाद करती हैं,तब यह भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि वे मनुष्य का स्थान ले सकती हैं। वास्तव में चुनौती यह नहीं है कि मशीनें मनुष्य बन जाएंगी,बल्कि यह है कि कहीं मनुष्य स्वयं मशीनों की तरह व्यवहार करने न लगे। यदि जीवन का प्रत्येक निर्णय गणनात्मक दक्षता और आंकड़ों के आधार पर होने लगे,तो मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य हाशिये पर जा सकते हैं। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि क्या भविष्य में एक नई मानव संरचना का निर्माण होगा? विश्व के अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी चिंतक यह मानते हैं कि आने वाले दशकों में जैविक मनुष्य और डिजिटल तकनीक के बीच की दूरी लगातार कम होगी। मस्तिष्क और कंप्यूटर के प्रत्यक्ष संपर्क, कृत्रिम अंगों, स्मृति-विस्तार तकनीकों और जैव-तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक ऐसे युग की कल्पना की जा रही है जहां मनुष्य और मशीन का सम्मिलित स्वरूप विकसित हो सकता है। यह संभावना जितनी आकर्षक दिखाई देती है,उतनी ही चिंताजनक भी है। यदि तकनीकी रूप से उन्नत मनुष्य और सामान्य मनुष्य के बीच गहरी खाई बन गई तो सामाजिक असमानता का एक नया रूप सामने आ सकता है।

एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में नियमित और दोहराव वाले कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त हो जाएंगे। विश्व की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों ने लागत कम करने और उत्पादकता बे ाने के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटाई है। किंतु हाल के अनुभव यह भी बताते हैं कि एआई मानव श्रम का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकी है। जटिल निर्णय,नवाचार, मानवीय संबंधों का प्रबंधन और

परिस्थितिजन्य विवेक जैसे क्षेत्रों में मनुष्य की भूमिका अभी भी केंद्रीय बनी हुई है। यहीं पर वैश्विक शोध संस्था गार्टनर की हालिया रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है। गार्टनर ने अपनी नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि एआई अब अत्यधिक अपेक्षाओं के शिखर से आगे बढ़कर मोहभंग के चरण में प्रवेश कर रही है। अनेक कंपनियों ने इससे तत्काल आर्थिक लाभ और उत्पादकता में चमत्कारी वृद्धि की उम्मीद की थी,लेकिन वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिले। परियोजनाओं की ऊंची लागत, आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, गलत या भ्रामक उत्तर देने की प्रवृत्ति और स्पष्ट उपयोगिता सिद्ध न कर पाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि लगभग एक-तिहाई परियोजनाएं प्रारंभिक चरण के बाद बंद हो सकती हैं क्योंकि वे अपने निवेश के अनुरूप परिणाम देने में असफल रही हैं। यह निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्काल सभी समस्याओं का समाधान बन जाएगी।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि एआई एक अस्थायी बुलबुला है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति के प्रारंभिक चरण में उत्साह और अतिशयोक्ति दोनों मौजूद रहते हैं। बाद में वास्तविक उपयोगिता के आधार पर उसका संतुलित विकास होता है। इंटरनेट के साथ भी यही हुआ था। प्रारंभिक उत्साह के बाद अनेक कंपनियां समाप्त हो गई,लेकिन इंटरनेट स्वयं विश्व व्यवस्था का आधार बन गया। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। अतः इसका अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन भी उचित नहीं है और इसके शीघ्र समाप्त हो जाने की कल्पना भी यथार्थवादी नहीं है। व्यापार जगत में एआई की भूमिका निरंतर बढ़ेगी। उत्पादन,विपणन,ग्राहक सेवा,वित्तीय विश्लेषण और आपूर्ति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होगा। इससे कार्यों की गति और दक्षता बढ़ेगी,किंतु साथ ही कार्यबल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। भविष्य में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा,बल्कि समस्या समाधान,रचनात्मकता,नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक समझ जैसे गुण अधिक महत्वपूर्ण बनेंगे। इसलिए शिक्षा और कौशल विकास की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना होगा।

प्रशासनिक क्षेत्र में भी एआई शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की क्षमता रखती है। नीतिगत विश्लेषण, संसाधनों का वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का संचालन तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। यदि नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़ों का अत्यधिक संग्रह और विश्लेषण होने लगे तो निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए तकनीकी दक्षता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। सैन्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग सबसे अधिक चिंताजनक माना जा रहा है। स्वायत्त हथियार प्रणालियां, मानव रहित युद्धक उपकरण और लक्ष्य चयन करने वाली मशीनें युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल सकती हैं। यदि किसी मशीन को जीवन और मृत्यु का निर्णय करने की शक्ति मिल जाए तो नैतिक और मानवीय प्रश्न अत्यंत गंभीर हो जाएंगे। इसलिए विश्व स्तर पर ऐसी तकनीकों के नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।

इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव जीवन सुरक्षित, संतुलित और सार्थक कैसे बना रहे? इसका उत्तर तकनीक के विरोध में नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण उपयोग में निहित है। एआई को मानव जीवन का स्वामी नहीं,सहायक बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में नैतिकता,संवेदनशीलता, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देना होगा। मनुष्य की भावनात्मक बुद्धिमत्ता,करुणा,सहानुभूति और आध्यात्मिक चेतना ही वे क्षेत्र हैं जिन्हें कोई मशीन प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। साथ ही, वैश्विक स्तर पर ऐसे नियमों और नीतियों की आवश्यकता है जो एआई के विकास को मानव कल्याण की दिशा में नियंत्रित करें। यदि यह तकनीक केवल कुछ शक्तिशाली कंपनियों या राष्ट्रों के हितों तक सीमित रह गई तो असमानता और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत यदि इसका उपयोग शिक्षा,स्वास्थ्य,पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास के लिए किया जाए तो यह मानवता के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोल सकती है।

अंततः एआई न तो पूर्णतः वरदान है और न ही अनिवार्य रूप से अभिशाप। यह एक शक्तिशाली साधन है जिसकी दिशा और परिणाम मनुष्य के विवेक पर निर्भर करेंगे। चुनौती मशीनों से नहीं, बल्कि इस बात से है कि क्या मनुष्य अपनी मानवीयता, संवेदनशीलता और नैतिक चेतना को सुरक्षित रख पाएगा। भविष्य का प्रश्न यह नहीं है कि एआई कितनी शक्तिशाली होगी, बल्कि यह है कि मनुष्य कितना सजग, उत्तरदायी और मूल्यनिष्ठ बना रहेगा। यदि मानवता तकनीकी प्रगति और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सकी, तो एआई मानव विकास का नया अध्याय लिखेगी अन्यथा वही तकनीक असंतुलन,असमानता और अस्तित्वगत संकट का कारण भी बन सकती है। यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

जब ट्रेंड तय करने लगे जनमत

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनमत होता है। यह जनमत किसी एक दिन या एक चुनाव के दौरान निर्मित नहीं होता, बल्कि समाज में निरंतर चलने वाले संवाद,बहस,विचार-विमर्श,सामाजिक अनुभवों,राजनीतिक चेतना और नागरिक भागीदारी की लंबी प्रक्रिया से आकार लेता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का सूचित निर्णय, विभिन्न विचारों का आदान-प्रदान और असहमति के प्रति सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लंबे समय तक भारत में जनमत के निर्माण का आधार प्रत्यक्ष संवाद, जनसभाएँ, सामाजिक संगठन, समाचार-पत्र, पुस्तकें, शिक्षण संस्थान और जनआंदोलन रहे। लेकिन डिजिटल क्रांति के बाद यह परिदृश्य तेजी से बदला है। आज सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह जनमत निर्माण की सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। ऐसे समय में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अब जनमत नागरिकों के स्वतंत्र चिंतन से अधिक सोशल मीडिया ट्रेंड और एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित होने लगा है?

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल उपभोक्ता समूहों में से एक भी। करोड़ों लोग प्रतिदिन फेसबुक, इंस्टाग्राम,एक्स, यूट्यूब,व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल मंचों का उपयोग करते हैं। समाचारों से लेकर राजनीतिक विचारों तक,समाज के बड़े वर्ग की प्राथमिक जानकारी अब इन्हीं प्लेटफॉर्मों से प्राप्त होती है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं,बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले जहाँ नागरिक किसी मुद्दे पर अखबार पढ़कर,बहस सुनकर या स्थानीय स्तर पर चर्चा करके राय बनाते थे,वहीं अब राय निर्माण की प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल मंचों पर निर्भर हो गई है। इस प्रक्रिया में सोशल मीडिया एल्गोरिदम की भूमिका केंद्रीय हो गई है।

एल्गोरिदम ऐसे तकनीकी तंत्र हैं जो यह तय करते हैं कि किसी उपयोगकर्ता को कौन-सी सामग्री दिखाई जाएगी और कौन-सी नहीं। वे उपयोगकर्ता की पसंद, गतिविधियों, खोज इतिहास और ऑनलाइन व्यवहार का विश्लेषण करके सामग्री का चयन करते हैं। तकनीकी दृष्टि से उनका उद्देश्य उपयोगकर्ता को अधिक समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना होता है,क्योंकि डिजिटल कंपनियों का आर्थिक मॉडल इसी पर आधारित है। लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से यह प्रक्रिया कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि नागरिकों को वही सामग्री दिखाई जाए जो उनकी पूर्व मान्यताओं से मेल खाती हो,तो क्या वे विविध विचारों से परिचित हो पाएँगे? यदि एल्गोरिदम यह तय करने लगें कि कौन-सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो क्या लोकतांत्रिक विमर्श स्वतंत्र रह पाएगा?

आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना किसी विषय की लोकप्रियता का प्रमुख संकेतक माना जाता है। कोई हैशटैग लाखों बार साझा हो जाए तो वह राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो ट्रेंड कर रहा है वही जनभावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि ट्रेंड वास्तव में समाज की व्यापक राय का प्रतिबिंब हो। अनेक बार ट्रेंड संगठित डिजिटल अभियानों,राजनीतिक प्रचार, भुगतान आधारित प्रचार रणनीतियों या बॉट नेटवर्क द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल दृश्यता और वास्तविक जनसमर्थन हमेशा समानार्थी नहीं होते। जमीनी स्तर की राजनीतिक भागीदारी और डिजिटल सक्रियता के बीच का अंतर भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत का लोकतांत्रिक इतिहास प्रत्यक्ष जनसहभागिता के अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने जेल यात्राएँ कीं,सत्याग्रह किए और सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत जोखिम उठाए। बाद के दशकों में भी अनेक आंदोलनों ने नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से संगठित किया। इन आंदोलनों में लोगों के बीच संवाद,विश्वास और सामूहिकता का निर्माण होता था। इसके विपरीत डिजिटल सक्रियता अक्सर प्रतीकात्मक भागीदारी तक सीमित रह जाती है। किसी पोस्ट को साझा करना, किसी हैशटैग का समर्थन करना या प्रोफाइल फोटो बदलना आसान है,लेकिन यह हमेशा वास्तविक सामाजिक हस्तक्षेप में परिवर्तित नहीं होता। परिणामस्वरूप राजनीतिक भागीदारी का एक नया स्वरूप विकसित हुआ है जिसमें दृश्यता अधिक और प्रत्यक्ष सामाजिक प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है।

सोशल मीडिया एल्गोरिदम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव तथाकथित इको चैंबर और फिल्टर बबल के रूप में सामने

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

आता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की सामग्री देखता या पसंद करता है, तो एल्गोरिदम उसे उसी प्रकार की और सामग्री दिखाने लगते हैं। धीरे-धीरे वह व्यक्ति ऐसे डिजिटल वातावरण में पहुँच जाता है जहाँ उसे मुख्यतः वही विचार दिखाई देते हैं जिनसे वह पहले से सहमत होता है। इससे वैचारिक विविधता कम हो जाती है और विरोधी विचारों के प्रति असहिष्णुता बढ़ने लगती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने और समझने के लिए तैयार हों। लेकिन यदि एल्गोरिदम नागरिकों को वैचारिक रूप से अलग-अलग खेमों में बाँट दें,तो लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है।

भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक समूह अपने-अपने डिजिटल समुदायों में सक्रिय रहते हैं। इन समुदायों के भीतर साझा की जाने वाली सामग्री अक्सर एक विशेष दृष्टिकोण को पुष्ट करती है और विरोधी विचारों को संदेह, उपहास या शत्रुता की दृष्टि से प्रस्तुत करती है। इससे समाज में संवाद की जगह टकराव की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक और आवश्यक है,लेकिन जब असहमति संवाद के बजाय वैमनस्य का रूप लेने लगे तो लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर पड़ने लगती है।

फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार का प्रश्न भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम से गहराई से जुड़ा हुआ है। एल्गोरिदम उन सामग्रियों को अधिक बढ़ावा देते हैं जिन पर लोग तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। अक्सर भावनात्मक और सनसनीखेज सामग्री तथ्यात्मक और संतुलित सामग्री की तुलना में अधिक तेजी से फैलती है। यही कारण है कि झूठी खबरें,आधे-अधूरे तथ्य,भ्रामक वीडियो और मनगढ़ंत दावे सोशल मीडिया पर अत्यंत तेजी से वायरल हो जाते हैं। भारत में कई अवसरों पर फेक न्यूज़ ने सामाजिक तनाव,सांप्रदायिक विवाद और सार्वजनिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की है। चुनावी राजनीति में भी गलत सूचनाओं का उपयोग मतदाताओं की राय को प्रभावित करने के लिए किया जाता रहा है। जब नागरिकों के निर्णय तथ्यात्मक जानकारी के बजाय दुष्प्रचार पर आधारित होने लगें,तो लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

सोशल मीडिया ने राजनीतिक संचार को भी पूरी तरह बदल दिया है। पहले राजनीतिक दलों को जनता तक पहुँचने के लिए रैलियों,सभाओं,पोस्टरों और पारंपरिक मीडिया का सहारा लेना पड़ता था। अब वे सीधे नागरिकों के मोबाइल फोन तक पहुँच सकते हैं। यह सुविधा लोकतंत्र के लिए सकारात्मक भी है क्योंकि इससे सूचना का प्रवाह तेज हुआ है। लेकिन इसके साथ ही माइक्रो-टार्गेटिंग जैसी नई रणनीतियाँ भी विकसित हुई हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के व्यवहार से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा एकत्र करते हैं। इस डेटा के आधार पर अलग-अलग समूहों को अलग-अलग राजनीतिक संदेश भेजे जा सकते हैं। इससे राजनीतिक प्रचार अधिक प्रभावी तो हो जाता है,लेकिन पारदर्शिता कम हो जाती है। नागरिकों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें जो संदेश दिखाया जा रहा है, वही संदेश अन्य नागरिकों को भी दिखाई दे रहा है या नहीं। लोकतंत्र का आदर्श सार्वजनिक और खुला विमर्श है, जबकि माइक्रो-टार्गेटिंग राजनीतिक संवाद को खंडित और निजी बना सकती है।

हालाँकि सोशल मीडिया और एल्गोरिदम के प्रभाव को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। इन मंचों ने अनेक सकारात्मक अवसर भी प्रदान किए हैं। समाज के हाशिए पर स्थित समूहों, महिलाओं, युवाओं,ग्रामीण समुदायों और अल्पप्रतिनिधित्व वाले वर्गों को अपनी बात रखने का नया मंच मिला है। कई सामाजिक मुद्दे जो पहले मुख्यधारा मीडिया में पर्याप्त स्थान नहीं पाते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय बहस का विषय बने हैं। डिजिटल माध्यमों ने सूचना तक पहुँच को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है और नागरिकों को सत्ता से सीधे संवाद करने का अवसर दिया है। कई जनहित अभियानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक समर्थन प्राप्त किया है। प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक आंदोलनों और जनजागरूकता अभियानों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की सकारात्मक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब तकनीकी मंच स्वयं लोकतांत्रिक विमर्श के निर्णायक बनने लगते हैं। किसी लोकतंत्र में यह निर्णय नागरिकों और संस्थाओं का होना चाहिए कि कौन-से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, न कि किसी निजी कंपनी के एल्गोरिदम का। लेकिन व्यवहार में कई बार यही होता दिखाई देता है कि जो विषय एल्गोरिदमिक रूप से अधिक दृश्यता प्राप्त कर लेता है, वही सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ जाता है। इससे उन महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है जो डिजिटल रूप से आकर्षक नहीं हैं,लेकिन सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण संकट, श्रमिक अधिकार, शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन जैसे विषय अक्सर मनोरंजक या विवादास्पद सामग्री की भीड़ में दब जाते हैं।

भारत जैसे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह डिजिटल तकनीक के लाभों को स्वीकार करते हुए उसके दुष्प्रभावों को कैसे नियंत्रित करे। इसके लिए केवल सरकारी नियमन पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि नागरिक सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकें। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता तथा तथ्य-जाँच संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपने एल्गोरिदम की पारदर्शिता और जवाब देही बढ़ानी होगी। राजनीतिक विज्ञापनों और डिजिटल प्रचार अभियानों के लिए स्पष्ट नियमों की आवश्यकता है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता बनी रहे। स्वतंत्र मीडिया, नागरिक समाज और शैक्षणिक संस्थानों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र केवल तकनीक से संचालित नहीं हो सकता। तकनीक लोकतंत्र का साधन हो सकती है,उसका विकल्प नहीं। सोशल मीडिया नागरिकों को जोड़ सकता है, लेकिन वह वास्तविक सामाजिक संबंधों और जमीनी भागीदारी का स्थान नहीं ले सकता। किसी पोस्ट को साझा करना और किसी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी हैशटैग को ट्रेंड कराना और समाज में स्थायी परिवर्तन लाना भी समान नहीं हैं। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति अभी भी जागरूक नागरिकों, स्वतंत्र चिंतन, सार्वजनिक संवाद और सामूहिक भागीदारी में निहित है।

अहंकार के जूते,त्याग के पाँव

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

बैठकखाने की दीवार पर टंगे बाबूजी के सनद, उनकी डिग्रियां ऐसे चमकती हैं जैसे किसी सामंती राजा के जीते हुए किले के नक्शे हों। बाबूजी एम.ए., एलएल.बी. हैं। उनका रुआब ऐसा है कि जब वे चाय मांगते हैं, तो लगता है जैसे हाईकोर्ट का कोई समन जारी हुआ हो। अम्मा उस समन की तामील रसोई के उस तंग, चार-बाय-चार के ब्लैक होल में करती हैं, जहां से लगातार छौंक की गंध और मसालों की जुगलबंदी उठती रहती है। वह कड़ाही और करछुल के बीच ऐसे युद्ध लड़ती हैं जैसे पानीपत की चौथी लड़ाई उन्हीं के जिम्मे हो। दाल में नमक जरा सा कम हुआ नहीं कि बाबूजी कानूनी किताब के पन्नों की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। अम्मा बस आंचल का कोना उंगली पर लपेटती हैं, थोड़ा मुस्कुराती हैं और एक चुटकी नमक डालकर पूरे केस को रफा-दफा कर देती हैं। मध्यवर्गीय घरों में डिग्रियां दीवारों पर मुस्कुराती हैं और योग्यता रसोई के बर्तनों के मांजने की आवाज में छिपी रहती है। बाबूजी महीने के आखिरी हफ्ते में बजट का रोना रोते हुए ऐसे दिखते हैं जैसे देश के वित्त मंत्री बिना रिजर्व बैंक के बैठे हों, लेकिन अम्मा अपनी फटी हुई मखमली डिबिया से चुपके से दो सौ के मुड़े-गले नोट निकाल लाती हैं। उनका यह अर्थशास्त्र एडम स्मिथ की छाती पर मूंग दलने के लिए काफी है, पर वे कभी इसका क्रेडिट नहीं लेतीं।

ये पैसे कहां से आए? बाबूजी ऐनक के ऊपर से घूरते।

बस,ऐसे ही...बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया, अम्मा नजरें चुराकर कहतीं।

तुम्हें तो अर्थशास्त्र का ककहरा भी नहीं पता, बस तुक्का लग जाता है, बाबूजी फाइल समेटते हुए बड़बड़ाते।

बाबूजी की नजर में अम्मा एक ऐसी अनपढ़ मशीन थीं,जो बिना किसी तेल-पानी के बस चलती जा रही थीं। जब अम्मा को सूखी खांसी उठती, तो डॉक्टर साहब ने पांच सौ की फीस और दो हजार की दवाइयां लिख दी थीं। बाबूजी ने बटुआ देखा, फिर अम्मा को। अम्मा ने पर्चा लिया,उसे मुट्ठी में भींचकर सीधे कचरे डिब्बे के सुपुर्द कर दिया। रात को दांत के नीचे एक लौंग दबाई और सुबह तक खांसी का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। बाबूजी ने कहा,यह सिर्फ अंधविश्वास और देहाती तुक्का है, मेडिकल साइंस के आगे इसकी क्या औकात! अम्मा चुप रहीं। वे हमेशा चुप रहती थीं,जैसे मौन ही उनका सबसे बड़ा थीसिस हो। जब घर का सिंगल बेडरूम स्पेस क्रंच की बीमारी से जूझता, तो अम्मा पुरानी बोतलों को काटकर उसमें मनीप्लांट ऐसे टांग देती थीं,मानो किसी पांच सितारा होटल की लॉबी हो। बाबूजी इसे कबाड़ का जमावड़ा कहते। अम्मा तब भी हंसती थीं। उनकी हंसी में एक अजीब सा दर्शन था। वे हर त्रासदी को एक मंद मुस्कान से निगल जाती थीं, जैसे नीलकंठ ने विष पिया हो।

अम्मा, तुमने कहां तक पढ़ाई की है? एक शाम मैंने उनकी फटी बिवाइयों वाले पैरों को देखते हुए पूछ ही लिया।

अरे, हम तो बस छठी गिलासी हैं बाबू, उन्होंने अपनी साड़ी के पैबंद लगे छोर से माथा पोंछते हुए कहा।

फिर यह सब कैसे कर लेती हो?

पेट की पाठशाला में कोई क्लास नहीं होती बेटा, वहां सीधे इम्तिहान होता है उन्होंने कड़ाही चढ़ाते हुए कहा।

बाबूजी की वकालत और ऊंची डिग्रियां तब धरी की धरी रह गई,जब अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब यह कभी बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। घर की डिग्रियां अचानक मूक दर्शक बन गईं। तब अम्मा ने अपनी उस छठी गिलासी वाली देह को एक खूंटे की तरह गाड़ दिया। वे दिन-रात बाबूजी के बिस्तर के पास बैठी रहतीं,उनके घाव धोतीं,उन्हें गोद में उठाकर वैसे ही सहलातीं जैसे किसी नवजात शिशु को संभाला जाता है। बाबूजी की आंखों का अहंकार अब पानी बनकर बह रहा था। एक रात, जब पूरा घर सन्नाटे की चादर ओढ़े सोया था,मैंने अम्मा को बाबूजी के सिरहाने बैठकर उनकी बरसों पुरानी सुनहरी जिल्द वाली एलएल.बी. की डिग्री को हाथ में लिए देखा। रोशनी मद्धिम थी। अम्मा बड़े ध्यान से उस डिग्री पर उंगलियां फेर रही थीं। मुझे लगा कि शायद वे बाबूजी के गौरव को याद कर रो रही हैं। अम्मा रो नहीं रही थीं। वे तो बस अपनी साड़ी के उसी पैबंद लगे छोर से बाबूजी का मुँह पोंछ रही थीं। तभी बाबूजी ने आँखें खोलीं और अम्मा का वह फटी बिवाइयों वाला खुरदरा हाथ पकड़कर अपने गाल से चिपका लिया। बरसों का वह कड़क रुआब और फासला उस एक छुअन में पिघलकर बह गया। बाबूजी की काँपती आवाज़ में बस इतना निकला, मुझसे बहुत भूल हुई...अम्मा ने कुछ नहीं कहा,उन्होंने झट से अपना दूसरा हाथ बाबूजी के होंठों पर रख दिया,मानो कह रही हों कि अब बस करो। उन्होंने बाबूजी को थोड़ा और समेटकर अपने सीने से लगा लिया।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

नायब तहसीलदार ने नार्को टेस्ट की मांग की,विधायक बोले...जांच के लिए तैयार...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर के राजापुर उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक और सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विधायक की बहन सीमा धनकी से कथित बदसलूकी और इसके बाद नायब तहसीलदार से मारपीट के मामले में दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज है। इसी बीच प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार विधायक व उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 जून से कामबंद-कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक की बहन या किसी महिला के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है। उन्होंने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए शासन से नार्को टेस्ट कराने की मांग करते हुए कहा कि सबसे पहले उनका नार्को टेस्ट कराया जाए,इसके बाद विधायक, उनकी बहन और मामले से जुड़ी एक अन्य महिला का भी परीक्षण कराया जाए। उनका कहना है कि इससे पूरे प्रकरण की वास्तविकता सामने आ जाएगी। तुषार मानिक ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई शासन से नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए है। उन्होंने उच्च स्तरीय मजिस्ट्रियल जांच की मांग करते हुए कहा कि जब तक विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।

प्रशासनिक सेवा संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी : नायब तहसीलदार तुषार मानिक से कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की सरगुजा इकाई ने दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में संघ ने कहा है कि 27 मई को नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ हुई घटना से जिले के प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारी-कर्मचारी आहत हैं। संघ का आरोप है कि अब तक मामले में अपेक्षित और संतोषजनक वैधानिक कार्रवाई नहीं होने से अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। संघ ने निर्णय लिया है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर 1 से 3 जून तक तीन दिनों तक अधिकारी एवं कर्मचारी काली पट्टी लगाकर नियमित शासकीय कार्य करते हुए शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराएंगे। यदि इस अवधि में भी विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद दो दिन का सामूहिक अवकाश लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आंदोलन का समर्थन किया जाएगा। साथ ही आगे की रणनीति की घोषणा अलग से की जाएगी।

जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं : विधायक

इधर विधायक रामकुमार टोप्पो ने भी नार्को टेस्ट कराने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे शुरू से ही निष्पक्ष जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जो भी जांच कराई जाएगी,वे उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। विधायक ने कहा कि यदि नार्को टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वे उसके लिए भी सहमत हैं और जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनने देंगे।

कला केन्द्र मैदान में दिया धरना

घटना के विरोध में सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक (आरआई) और पटवारी संगठन आंदोलनरत हैं। हड़ताल के कारण तहसील कार्यालयों में राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरगुजा में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलाकेन्द्र मैदान में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई।

डीके सोनी का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यों को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी को उनके जनहित,सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। डॉ. सोनी का नाम 'लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज किया गया है। उन्हें यह सम्मान यूनाइटेड किंगडम के डॉक्टर यूरोपियन यूनियन हेड रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया एवं इंटरनेशनल चेयरमैन इंडिया अविनाश डी. सकुंदेया के करकमलों से प्रदान किया गया।

डॉ. डीके सोनी लंबे समय से न्याय में देरी, भ्रष्टाचार और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वे अपनी संस्था 'सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस' के माध्यम से आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आरटीआई और जनहित याचिकाओं के माध्यम से उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों को उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उठाया और सफल कानूनी लड़ाइयाँ लड़ीं। डॉ. सोनी ने सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने में भी अहम भूमिका निभाई है। दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर कई मामलों में कार्रवाई कराते हुए भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराने में सफलता हासिल की है। देशभर में सामाजिक, कानूनी, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे। चयन प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद,आदिवासी हित, शासन हित और जनहित में उल्लेखनीय योगदान देने पर डॉ. डी.के. सोनी को यह सम्मान प्रदान किया गया।

दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मान पत्र भेंट किया गया। डॉ. डी.के. सोनी को यह सम्मान मिलने पर उनके शुभचिंतकों, अधिवक्ताओं और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाले लोगों में हर्ष का माहौल है।

लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर डॉ. सोनी ने कहा कि यह सम्मान उन्हें जनहित और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में और अधिक ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने भविष्य में भी समाजहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने की बात कही।

मजदूरी का पैसा मांगने पहुंचे युवकों पर हमला,लोहे की रॉड से की मारपीट

-संवाददाता-
लखनपुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोरजा में मजदूरी का बकाया भुगतान मांगने पहुंचे दो युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम कोरजा निवासी रामकुमार पैकरा, पिता राजाराम कंवर, स्थानीय निवासी राकेश यादव के यहां ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करता था। उसकी कई महीनों की मजदूरी बकाया थी। मजदूरी की राशि लेने के लिए रामकुमार ने 30 मई को राकेश यादव को फोन किया। बातचीत के दौरान शाम को भुगतान करने की बात तय हुई। रात करीब 8.30 बजे रामकुमार अपने रिश्तेदार विजय पैकरा के साथ राकेश यादव के घर पहुंचा। आरोप है कि उस समय राकेश यादव शराब के नशे में था। मजदूरी के पैसे मांगने पर वह भड़क गया और दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और राकेश यादव ने लोहे की रॉड से रामकुमार और विजय पर हमला कर दिया। हमले में रामकुमार गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया, जबकि विजय के हाथ, पैर और गर्दन में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद परिजन दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया। पीड़ितों की शिकायत पर लखनपुर पुलिस ने आरोपी राकेश यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

करैत सांप के डंसने से वृद्धा की मौत,10 दिन तक चला इलाज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदरपुर गांव में करैत सांप के डंसने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। सांप के काटने के बाद महिला का लगातार इलाज चल रहा था,लेकिन 10 दिन बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार आलोरानी पाल (71 वर्ष), पति स्वर्गीय निरंज पाल,मूल रूप से कांकेर जिले के नवापल्ली थाना परवानपुर क्षेत्र की निवासी थीं। वह पिछले एक वर्ष से अपनी बेटी और दामाद के साथ दामोदरपुर गांव में रह रही थीं। बताया गया कि 21 मई की रात भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में सो रही थीं। रात करीब 12:30 बजे अचानक उनकी चीख सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे।

विश्व तम्बाकू दिवस के अवसर पर जागरूकता रथ रवाना,तम्बाकू मुक्त जीवन का दिया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में तम्बाकू एवं धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट-गाइड, एनएसएस, एनसीसी एवं रेडक्रास सोसाइटी के छात्र-छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकालकर आमजन को तम्बाकू मुक्त जीवन का संदेश दिया गया। कलेक्टर वसंत ने कहा कि तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थ आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू केवल शरीर को बीमार नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की मेहनत की कमाई को भी नशे और बीमारियों के इलाज पर खर्च कराकर आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं तम्बाकू एवं धूम्रपान से दूर रहें तथा अपने परिवार और समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को ने बताया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके आसपास रहने वाले लोग भी सेकंड हैंड स्मोकिंग से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तम्बाकू सेवन से मुख कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, सीओपीडी तथा सांस संबंधी अनेक गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू मुक्त जीवन ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला है।नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि तम्बाकू सेवन विश्व में समय पूर्व मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। धूम्रपान छोड़ने के कुछ ही घंटों के भीतर शरीर में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं।

पुरानी रंजिश में दो युवकों से मारपीट 2100 रुपये लूटने का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

शहर के प्रकाश अस्पताल के पास 29 मई की देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देवीगंज रोड निवासी 24 वर्षीय सृजन सिंह 29 मई की रात करीब 2.30 बजे अपने दोस्तों सोहेल मंसूरी, अक्ता रिजवी और विक्की के साथ किसी काम से माता राजरानी अस्पताल गया था। इस दौरान सृजन और सोहेल प्रकाश अस्पताल के सामने मुख्य सड़क पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, जबकि उनके अन्य साथी अस्पताल के अंदर थे। इसी बीच अंश पंडित, चितु पंडित तथा उनके दो अन्य साथी वहां पहुंचे। आरोप है कि सभी के हाथों में चाकू, ईंट और पत्थर थे। पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने सृजन और सोहेल के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और 'हमको जेल भिजवाओगे' कहते हुए हमला कर दिया।

राष्ट्रीय रैपिड शतरंज प्रतियोगिता के विजेता बने संस्कार कश्यप

जीएच रायसोनी मेमोरियल ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का समापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

जीएच रायसोनी मेमोरियल ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता-2026 का समापन रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ। भारतीय शतरंज महासंघ एवं छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को कुल 51 हजार रुपए की नगद पुरस्कार राशि और ट्रॉफियां प्रदान की गईं। मुख्य वर्ग में संस्कार कश्यप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उन्हें 11 हजार रुपए नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी दी गई। अभिषेक राजवाड़े दूसरे और गौरव साहू तीसरे स्थान पर रहे। संजय भारद्वाज चौथे तथा शुभंकर बमालिया पांचवें स्थान पर रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का अंबिकापुर में आयोजन सरगुजा के लिए गौरव की बात है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी बेहतर मंच मिला है।

ये रहे विजेता : आयु वर्ग प्रतियोगिताओं में अंडर-15 बालक वर्ग में हिमांनिस तिर्की, अंडर-13 में जय वर्धन भार्गव, अंडर-11 में चनवीर सिंह, अंडर-9 में अपूर्व भार्गव और अंडर-7 में प्रज्वल पांडे विजेता रहे।

बालिका वर्ग में अंडर-15 में फरहीन खान, अंडर-13 में निष्ठा त्रिपाठी, अंडर-11 में शताक्षी गुप्ता, अंडर-9 में अनिका गुप्ता तथा अंडर-7 में शिल्पी तानिष्का ने पहला स्थान प्राप्त किया। समारोह में विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक इंटरनेशनल आर्बिटर अनीस अंसारी थे।

30 दिन से अनुपस्थित नेत्र सहायक अधिकारी निलंबित..औचक निरीक्षण में गैरहाजिर मिले,नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पम्पापुर में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी मोहम्मद शाहिद हुसैन को लंबे समय से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने की है। जानकारी के अनुसार 26 मई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पम्पापुर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शाहिद हुसैन करीब 30 दिनों से अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय वे ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे और उपस्थिति पंजी में भी उनके हस्ताक्षर दर्ज नहीं मिले। इसके बाद विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। खंड चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर ने भी बताया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा अवकाश के संबंध में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। नोटिस की जानकारी फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजी गई।

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का उत्सव,85 प्रतिशत मतदान

15 वार्डों में मतदाताओं ने दिखाया उत्साह,4 जून को आएगा जनादेश

-संवाददाता-
सूरजपुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत के प्रथम आम निर्वाचन में मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी आस्था का परिचय देते हुए रिकॉर्ड 85.13 प्रतिशत मतदान किया, नगर पंचायत के 15 वार्डों में सोमवार को शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ, मतदान समाप्त होने के साथ ही अध्यक्ष एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है, जिसका फैसला 4 जून को मतगणना के दौरान सामने आएगा।

महिलाओं और पुरुषों की बराबर भागीदारी-प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 3952 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इनमें 1991 पुरुष मतदाता शामिल रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 85.26 रहा, वहीं 1961 महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जो कुल महिला मतदाताओं का 85 प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत में पुरुषों और महिलाओं की लगभग समान भागीदारी लोकतंत्र के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है।

मतदान केंद्रों पर दिखा उत्साह-सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं, युवा मतदाताओं के साथ-साथ बुजुर्गों और महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर मतदान किया, कई मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला, शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न होने से प्रशासन और निर्वाचन अमले ने राहत की सांस ली।

प्रशासनिक व्यवस्था रही चुस्त-दुरुस्त- मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती रही तथा अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी, जिले के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विनय कुमार अग्रवाल ने भी विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम शिवानी जायसवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

पंचायत उप निर्वाचन भी हुआ संपन्न-नगर पंचायत चुनाव के साथ जिले के विभिन्न विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, इसके अंतर्गत 2 जनपद पंचायत सदस्य, 3 सरपंच तथा 6 पंच पदों के लिए मतदान कराया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

अब 4 जून पर टिकी निगाहें-मतदान समाप्त होने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में चुनावी परिणामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, अब सभी की निगाहें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब ईवीएम में कैद मतदाताओं का फैसला सामने आएगा और यह तय होगा कि नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत की कमान आखिर किसके हाथों में जाएगी।

कलेक्टर ने जताया आभार-मतदान संपन्न होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रेना जमील ने सभी मतदाताओं, निर्वाचन कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी है।

सुबह 6 बजे सड़क पर उतरीं कलेक्टर,गुणवत्ता जांच ने बढ़ाई उम्मीदें...अब गोबरी नदी पुल पर भी निगाहों का इंतजार...

कागज नहीं,जमीन पर जांच...कलेक्टर रेना जमील ने खुद खोदकर देखी सड़क की गुणवत्ता...

- सड़कों की परतें नापीं,कॉम्पैक्शन जांचा... कलेक्टर का सख्त रुख देख ठेकेदारों में हलचल...
- निर्माण में समझौता नहीं : तड़के निरीक्षण पर निकलीं कलेक्टर,अधिकारियों को दिया कड़ा निर्देश
- गुणवत्ता की पड़ताल के लिए मैदान में उतरीं कलेक्टर, अब गोबरी नदी पुल पर भी जनता की उम्मीदें...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर 01 जून 2026 (घटती-घटना)। जिले में लंबे समय से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उठते सवालों के बीच सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील का तड़के सुबह सड़कों पर उतरकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना चर्चा का विषय बना हुआ है,आमतौर पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन फाइलों, रिपोर्टों और बैठकों तक सीमित रह जाता है, लेकिन इस बार कलेक्टर स्वयं सुबह 6 बजे लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचीं, निरीक्षण के दौरान जिस तरह सड़क की चौड़ाई,ढलान, एलाइनमेंट और कॉम्पैक्शन की जांच की गई, यहां तक कि सड़क की खुदाई कर परतों की मोटाई भी जांची गई, उससे लोगों के बीच यह संदेश गया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन इस बार गंभीर दिखाई दे रहा है।

कलेक्टर ने मौके पर जांची सड़कों की असलियत-सूरजपुर,प्रेमनगर और रामानुजनगर क्षेत्र में हुए इस सघन निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं किया बल्कि निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता की भी जांच कराई, सड़क की प्रत्येक परत की मोटाई मानक अनुरूप है या नहीं, इसके लिए मौके पर खुदाई कराई गई, कॉम्पैक्शन की जांच हुई, जल निकासी की व्यवस्था देखी गई और निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, निर्माण एजेंसियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों को यह भी निर्देशित किया गया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं और तकनीकी मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो।

15 जून से पहले अधिकाधिक कार्य पूर्ण करने का निर्देश

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून शुरू होने से पहले अधिक से अधिक निर्माण कार्य पूरे किए जाएं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों की रीढ़ भी होती हैं,यही कारण है कि निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इन प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण मार्गों का निरीक्षण किया, जिनमें तिलसिवा से भैंसामार गोंड़पारा,लांची से सत्तीपारा,परशुरामपुर-उमेश्वरपुर मार्ग से मोहनपुर पंडोपारा, उमेश्वरपुर से पार्वतीपुर सरईपारा तथा सलका कर्मी टिकरा से लक्ष्मीपुर खास मार्ग शामिल रहे, इसके अलावा कंचनपुर से काशी कुर्रीपारा और प्रेमनगर रोड से राजाकछर तक के नवीनीकरण कार्यों का भी जायजा लिया गया, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत देवीपुर-महामाया पंडुम मार्ग,बड़ाकापाद-पम्पापुर-कोट-पटना मार्ग, उमेश्वरपुर-कुमरभवना मार्ग,वृंदावन-सलका मार्ग और नारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर मार्ग सहित कई निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

गोबरी नदी पुल पर बढ़ी निगरानी की मांग...

क्षेत्र के लोगों का मानना है कि गोबरी नदी पुल का मामला केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि हजारों ग्रामीणों के आवागमन, शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ा विषय है, बरसात करीब है और रपटा पुल की स्थिति को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है, ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद है कि कलेक्टर सड़कों की तरह इस मामले पर भी सीधे संज्ञान लेंगी और निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश जारी करेंगी।

जनता की उम्मीदें अब गोबरी नदी पुल पर भी...

कलेक्टर के इस निरीक्षण के बाद जिले में एक नई चर्चा शुरू हो गई है, लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह सड़कों की गुणवत्ता की जांच स्वयं कलेक्टर ने की है, उसी तरह गोबरी नदी पर बन रहे स्थायी पुल और लंबे समय से अधूरे पड़े रपटा पुल के मामले को भी गंभीरता से लिया जाएगा, गोबरी नदी का मामला पिछले कई महीनों से चर्चा में है, पुराना पुल टूटे लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक रपटा पुल अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। दूसरी ओर 3 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से स्थायी पुल का निर्माण भी जारी है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंच सकती हैं, तो गोबरी नदी पुल की वास्तविक स्थिति का भी निरीक्षण होना चाहिए,इससे न केवल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता स्पष्ट होगी बल्कि कार्य की गति और जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी।

कलेक्टर की कार्यशैली ने बढ़ाया भरोसा

जिले में लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला है जब निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी स्वयं सुबह-सुबह मैदान में उतरा हो, यही वजह है कि लोगों के बीच यह संदेश गया है कि यदि शिकायतें और समाचार तथ्यात्मक हैं तो उन पर कार्रवाई भी संभव है,अब लोगों की नजरें गोबरी नदी पर टिक गई हैं,जहां अधूरा रपटा पुल,निर्माणाधीन स्थायी पुल और मानसून की दस्तक एक साथ कई सवाल खड़े कर रहे हैं,सड़कों की गुणवत्ता की जांच ने जहां जनता का भरोसा बढ़ाया है, वहीं अब यह उम्मीद भी मजबूत हुई है कि गोबरी नदी पुल मामले में भी जल्द कोई ठोस पहल देखने को मिल सकती है।

अतःगागर नदी में डूबे व्यक्ति की लाश स्वतः बाहर आई

-संवाददाता-

राजपुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना एवं बरियों चौकी क्षेत्र की सीमा में स्थित गागर नदी में डूबे 22 वर्षीय युवक फुलसाय लकड़ा का शव सोमवार सुबह बरामद कर लिया गया। दो दिनों तक चले लगातार खोज अभियान के बाद युवक का शव नदी के हक्कादह दरहा नामक स्थान पर पानी के बहाव के साथ ऊपर आ गया। जानकारी के अनुसार बरियों उरांव पारा में आयोजित शादी समारोह के बाद शनिवार सुबह फुलसाय लकड़ा (22 वर्ष), पिता सुरेंद्र लकड़ा,अपने साथियों के साथ गागर नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह नदी की गहराई में चला गया और डूब गया। घटना के बाद से राजपुर थाना पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा था। क्षेत्र में रविवार रात हुई तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ गया था। सोमवार सुबह लगभग 9 बजे ग्रामीणों ने हक्कादह दरहा के पास नदी में शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया

कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। युवक का शव मिलने के बाद परिजनों में शोक की लहर है तथा पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने लोगों से नदी, तालाब एवं अन्य गहरे जलाशयों में नहाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

एनएच-343 में मानकों के विपरीत हो रहे पेंच रिपेयरिंग कार्य के विरोध में 5 जून को धरना-प्रदर्शन एवं सांकेतिक चक्का जाम का सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-

राजपुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि दिनांक 1/6/2026को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय राजमार्ग-343 में राजपुर नगर क्षेत्र में किए जा रहे पेंच रिपेयरिंग कार्य की गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही थाना प्रभारी राजपुर को भी प्रस्तावित आंदोलन की सूचना दी गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि एनएच-343 की स्थिति पिछले लगभग दो वर्षों से अत्यंत जर्जर बनी हुई है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त हिस्सों के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों तथा राहगीरों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के नव निर्माण का कार्य अक्टूबर माह से प्रारंभ होने के बावजूद ठेकेदार की धीमी कार्यप्रणाली के कारण अब तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। वर्तमान में बरसात पूर्व कराए जा रहे पेंच रिपेयरिंग कार्य को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि यह कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप न होकर जेसीबी मशीन के माध्यम से

मनमाने ढंग से किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। इसको लेकर आम जनता में प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों के प्रति असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। नीरज तिवारी ने प्रशासन से मांग की है कि पेंच रिपेयरिंग कार्य की निष्पक्ष जांच कराकर निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई और कार्य में सुधार नहीं हुआ, तो जनहित में दिनांक 5 जून 2026, शुक्रवार को दोपहर 12 बजे राजपुर के नवकी मोड़ पर धरना-प्रदर्शन एवं सांकेतिक चक्का जाम किया जाएगा। आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित विभाग की होगी।

घर में खून से लथपथ मिली बुजुर्ग महिला की लाश

शरीर पर चोट के निशान,हत्या की आशंका,पुलिस जांच में जुटी

-संवाददाता-

लखनपुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)। थाना क्षेत्र के बेलदागी मुख्य मार्ग स्थित एक मकान में सोमवार सुबह 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान लक्ष्मी लकड़ा (70),पति बैजनाथ लकड़ा, निवासी लखनपुर के रूप में हुई है। सोमवार सुबह करीब 7.30 बजे घर में काम करने वाली युवती जब मकान पहुंची तो उसने महिला को खून से सनी अवस्था में पड़ा देखा। इसके बाद उसने आसपास के लोगों को सूचना

दी। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर लखनपुर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

हरसागर तालाब स्थित गुमटियों के आबंटन हेतु 15 जून तक आमंत्रित किए गए ऑफर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)। नगर पालिक निगम आयुक्त ने बताया कि नगर पालिक निगम के स्वामित्व की हरसागर तालाब के पास स्थित भूतल पर बनी गुमटियों का आबंटन निर्धारित प्रीमियम (जो कभी वापसी योग्य नहीं होगा) तथा मासिक किराये पर किये जाने हेतु स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा 15 जून 2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में शील्ड ऑफर आमंत्रित किये गए हैं। प्राप्त ऑफर 15 जून 2026 को ही उपस्थित ऑफरदाताओं के समक्ष अपरान्ह 04:30 बजे खोले जाएंगे तथा 12 जून 2026 तक ऑफर प्रपत्र का निर्धारित शुल्क भुगतान उपरान्त निगम के राजस्व कार्यालय (गौरवपथ स्थित प्रशासनिक भवन के राजस्व शाखा) से ऑफर प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी बलरामपुर

जिला- बरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/1442/ वि0विवाह अधि0/वाचक/2026 बलरामपुर दिनांक 15.05.2026

फार्म-अ

सार्वजनिक सूचना (नियम 6 देखिए)

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि वर पक्ष फिरदोश आ0 अमीनुदीन उम्र 29 वर्ष जाति जुलाहा निवासी ग्राम मेघुली पोष्ट चाकी पुलिस चौकी विजयनगर तहसील रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) के वधु पक्ष पुजा कुमारी सिंह पुत्री मनोज सिंह जाति खैरवार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मेघुली पोष्ट चाकी पुलिस चौकी विजयनगर तहसील रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत अपने विवाह के अनुष्ठापित किये जाने हेतु आशयित विवाह की सूचना उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुसूचि में प्रस्तुत किया है। जो संलग्न है। इस अनुष्ठापित होने वाले विशेष विवाह के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा आपत्ति हो तो इस उद्घोषणा के प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 15.06.2026 तक मेरे न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी ।

(सुनवाई दिनांक 15.06.2026)

(आर.एस.लाल)
अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी
बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

सील

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 / अ-6 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिकागण सोना कौर सिरे रविन्द्र सिंह सिरे, उम्र- 50 वर्ष, निवासी न्यू गुरूद्वारा गोविन्दनगर रायपुर, गुणिता देओरा पति जयंत सिंह देओरा, उम्र- 44 वर्ष, निवासी गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण की माता श्रीमती दलवीर बाबरा पति स्व. देवेन्द्र सिंह बाबरा के स्वामित्व व अधिवत्य की नगर अम्बिकापुर मोहल्ला कम्पनी बाजार शीट नं. 03 स्थित नजूल भूमि खसरा नं. 1349 / 6, 1349/7 रकबा क्रमशः $0.07^{3/4}$, $0.14^{1/4}$ एकड़ भूमि है। भूधारक श्रीमती दलवीर बाबरा पति स्व. देवेन्द्र सिंह बाबरा की मृत्यु दिनांक 25.12.2025 को हो गई है। अतः श्रीमती दलवीर बाबरा की मृत्यु हो जाने उपरांत उक्त भूमि से उनका नाम विलोपित कर स्वयं के नाम से फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदिकागण द्वारा मृतक भूधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 08/06/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं । नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक-18/05/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

सील

बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 12 घंटे में 22 स्थायी वारंटी गिरफ्तार,वर्षों से फरार आरोपी भी पकड़े

-संवाददाता-

बलरामपुर,01 जून 2026 (घटती-घटना)। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से बलरामपुर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान मात्र 12 घंटे के भीतर 22 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को लंबित स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटों के तामील हेतु विशेष

निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 1 जून 2026 को तड़के लगभग 3 बजे से थाना एवं चौकी स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान कई वर्षों से फरार चल रहे वारंटियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस की कार्रवाई में रामानुजगंज थाना से 4, कुसमी थाना से 4, कोतवाली बलरामपुर से 1, रघुनाथनगर से 3, बसंतपुर से 2, वाड्रफनगर चौकी से 2, चलगली से 1, रनहत चौकी से 1, चांदो थाना से 1, विजयनगर चौकी से 1, सनावल थाना से 1 तथा बरियों चौकी से 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर ,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

आगामी तिथि 25/6/2026

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक फातमा खान आ0 रहमतउल्लाह निवासी सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1972/2, 1974 /2 रकबा क्रमशः 1742, 871 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है। अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था / विभाग को कोई दावा / आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक / लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा / आपत्ति दिनांक 25/6/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 26/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
,सूरजपुर

सील

न्यायालय तहसीलदार सीतापुर, जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ग्राम बेलजोरा

ईश्तहार

समस्त हितबध्द पक्षकार को सूचित किया जाता है कि आवेदिकागण बूदा, रईला, मईलो, झीलो आ0 सुखना, जाति उरांव, सा0 बेलजोरा, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0 के द्वारा उनके एवं अना0 मंगरी, बालो, बसंती पुत्री लझरू तथा मु0 सुखमनिया बेवा लझरू, धनीराम, अनिराम आ0 घुरसाय, रीझो बेवा घुरसाय, जाति उरांव के नाम से ग्राम बेलजोरा, पटवारी हल्का कमांक-09, तहसील सीतापुर में स्थित भूमि कुल ख0नं0 06-361, 1631/2, 1641/2, 1725, 1731, 1733/1 कुल रकबा 2.252 हे0 वादभूमि के खातेदार अना0 की माता सुखमनिया बेवा लझरू की मृत्यु होने के कारण विलोपित किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेजों संहिता धारा 109, 110 छ0ग0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र में आवेदिकागण के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई दावा /आपत्ति हो तो लिखित में स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा दावा / आपत्ति दिनांक 05/06/2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
सीतापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शफीक निजामी आ0 हबीब निजामी निवासी मोमिनपुरा थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने पत्नी (स्व. आमना बेगम आ0 पति शफीक निजामी की दिनांक 27/01/2001 को स्थान निवास में मृत्यु हुई है।

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं दिलबसिया पति रामचरण उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम एच नं. 81, पटेलपारा कान्तिप्रकाशपुर अम्बिकापुर थाना व तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0। यह कि मेरे पुराने आधार कार्ड मे मेरा नाम दिलबसिया DIL-BASIYA अकिंत है जो सत्य व सही है। मेरे द्वारा आधार कार्ड को अपडेट कराया था जिसमे त्रुटिवश मेरा नाम KENDI अकिंत है गलत है।

उक्त नाम केन्दी KENDI के स्थान पर मेरे सही नाम दिलबसिया DIL-BASIYA अकिंत किया जाये जिसके लिये स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
दिलबसिया

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै वर्ष (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी शिव प्रसाद गाँव/शहर भदवाही, पो0 जामडीड तहसील-उदयपुर जिला -सरगुजा छ0ग0 ने अपना नाम वर्ष (पुराना नाम) से बदल कर वर्षा सिंह (नया नाम) रख लिया है।

आवेदक
वर्षा सिंह
भदवाही,पो0 जामडीड
तहसील-उदयपुर
जिला -सरगुजा छ0ग0

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै फुलसाय चेरवा (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री भागवत चेरवा गाँव/शहर कुदरगढ़ तहसील-ओड़गी जिला -सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम धूर साय (पुराना नाम) से बदल कर घूरन राम (नया नाम) रख लिया है।

पालक
फुलसाय चेरवा
कुदरगढ़ तहसील-ओड़गी
जिला -सूरजपुर छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै धरमेन्द्र सिंह पैंकरा (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री गोपाल राम गाँव/शहर पार्वतीपुर पो0 बरगीडीह तहसील-लुण्ड्रा जिला -सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम लिलेश कुमार (पुराना नाम) से बदल कर लियांश पैंकरा (नया नाम) रख लिया है।

पालक
धरमेन्द्र सिंह पैंकरा
पार्वतीपुर पो0 बरगीडीह
तहसील-लुण्ड्रा,सरगुजा छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै कुलसाय (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र तेजू राम गाँव/शहर मंझझार पारा ग्राम सखौली तहसील-धौरपुर जिला -सरगुजा छ0ग0 ने अपना नाम कुलसाय (पुराना नाम) से बदल कर फूल साय (नया नाम) रख लिया है।

आवेदक
फूल साय
मंझझार पारा ग्राम सखौली
तहसील-धौरपुर
जिला -सरगुजा छ0ग0

CMYK

11 महीने में नहीं बन पाया 15 लाख का रपटा, 3.60 करोड़ के पुल पर दौड़ रहे अफसर

गोबरी नदी में बह रहा विकास का सच

गोबरी नदी में विकास की दो रफ्तार,करोड़ों का पुल तेज,जनता का रपटा अधूरा

बरसात सिर पर,रपटा अधूरा-आखिर किसके भरोसे रहेगा आवागमन?

टूटा पुल, अधूरा रपटा और मौन व्यवस्था,11 महीने बाद भी नहीं मिला समाधान

जहां करोड़ों की मलाई,वहीं अधिकारियों की परछाई,15 लाख का रपटा भगवान भरोसे

एक दिन काम, दस दिन आराम,गोबरी नदी रपटा पुल निर्माण पर उठे सवाल

रपटा पुल की चाल कछुए जैसी,अधिकारियों की गाड़ी फर्राटे जैसी

जनता पूछ रही...पुल पहले बनेगा या फिर अगला मानसून आ जाएगा?

टूटा पुल देख रो रहे ग्रामीण,करोड़ों का पुल देख मुस्कुरा रहे जिम्मेदार

नेता आए, फोटो खिंचाए,आश्वासन दे गए-रपटा आज भी अधूरा रह गया

लापरवाही किसकी? विभाग की,ठेकेदार की या सिर्फ जनता की किस्मत खराब है?

-रवि सिंह-

सूरजपुर/कोरिया, 01 जून 2026 (घटती-घटना)। गोबरी नदी पर टूटे पुल की कहानी अब केवल एक निर्माण कार्य की देरी की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि यह सरकारी तंत्र,ठेकेदारी व्यवस्था,विभागीय उदासीनता और राजनीतिक प्राथमिकताओं की ऐसी जीवंत मिसाल बन गई है, जिसे देखकर ग्रामीणों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है आखिर उनकी परेशानी का जिम्मेदार कौन है? विभाग, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि या फिर वह व्यवस्था जो हर निरीक्षण के बाद आश्वासन देती है लेकिन जमीन पर कुछ बदलता नहीं, करीब 11 महीने पहले गोबरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, उस समय दावा किया गया था कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी और स्थायी पुल निर्माण की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज जब मानसून की आहट सुनाई देने लगी है,तब भी स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी पुल टूटने के समय थी, फर्क सिर्फ इतना है कि तब लोगों के पास उम्मीद थी, अब निराशा है।

गोबरी नदी पर विकास की दो तस्वीरें

वही उसी गोबरी नदी इस समय विकास की दो अलग-अलग तस्वीरें दिखा रही है, पहली तस्वीर बिरमताल से उमेशपुर मार्ग पर बन रहे लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपये के पुल की है, यहां मशीनें चल रही हैं, अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, ठेकेदार सक्रिय दिखाई देता है और काम की प्रगति भी नजर आती है, दूसरी तस्वीर उसी नदी पर बने टूटे हुए पुराने पुल और उसके स्थान पर बनाए जा रहे 15 लाख रुपये के रपटा पुल की है,यहां महीनों से काम रेंग रहा है, कभी मजदूर दिखते हैं तो कई दिनों तक काम बंद रहता है, कभी पाइप गिरा दिए जाते हैं तो कई सप्ताह तक कोई गतिविधि दिखाई नहीं देती,ग्रामीणों का कहना है कि लगता है जैसे करोड़ों का पुल विभाग और ठेकेदार दोनों का प्रिय प्रोजेक्ट है, जबकि 15 लाख का रपटा केवल मजबूरी में लिया गया काम है।

3.60 करोड़ के पुल में तेजी...15 लाख का रपटा अब भी अधूरा-गोबरी नदी पर विकास की दो रफ्तार

पुल टूटा 7 महीने से...रपटा फाइलों में-ठेकेदार बड़े काम में व्यस्त,छोटा काम उपेक्षित

पुल टूटा या व्यवस्था? गोबरी नदी पुल 7 महीने से टूटा पड़ा

समाधान अब भी फाइलों में रपटा भी भूमिपूजन के इंतजार में अटका

मानसून की दस्तक और बढ़ती चिंता...

सबसे बड़ी चिंता अब आने वाले मानसून को लेकर है, मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। बीच-बीच में बारिश भी हो रही है,यदि बरसात शुरू होने से पहले रपटा पुल तैयार नहीं हुआ तो पूरा क्षेत्र फिर से संपर्कहीन हो सकता है,लोगों को डर है कि पिछले 11 महीनों की परेशानी आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है।

पत्रों में कार्रवाई,जमीन पर इंतजार

विभागीय रिकॉर्ड में शायद बहुत सी कार्रवाई हो चुकी होगी, पत्र जारी हुए होंगे, स्पष्टीकरण मांगे गए होंगे,निरीक्षण रिपोर्ट तैयार हुई होंगी,लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पुल अभी भी अधूरा है, जनता को पत्र नहीं चाहिए,पुल चाहिए,ग्रामीणों को फाइलों की भाषा नहीं समझ आती,उन्हें सिर्फ इतना समझ आता है कि बरसात आने वाली है और उनका रास्ता अभी भी अधूरा पड़ा है।

सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी...

11 महीने पहले पुल टूटा था, 11 महीने बाद भी वैकल्पिक रपटा अधूरा है,एक ही ठेकेदार के पास दोनों काम हैं,करोड़ों वाले पुल पर तेजी है, लेकिन जनता की तत्काल जरूरत वाला काम अब भी अधूरा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गोबरी नदी पर प्राथमिकता किसे दी जा रही है–जनता को या बजट को? और यदि इस बार भी बरसात में आवागमन बंद हुआ,लोग फंसे,मरीज रास्ते में परेशान हुए और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए,तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्योंकि नदी तो हर साल बरसात में बढ़ती है,लेकिन इस बार सवाल पानी से ज्यादा उस व्यवस्था पर उठ रहे हैं जो 11 महीने में भी लोगों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार नहीं कर पाई।

एक ही ठेकेदार,लेकिन दो अलग-अलग रफ्तार...

सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों कार्यों की जिम्मेदारी एक ही ठेकेदार को दी गई है,जब 3.60 करोड़ रुपये वाले पुल पर काम लगातार चल सकता है तो फिर 15 लाख रुपये के रपटा पुल पर काम महीनों तक क्यों अटका रहता है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि रपटा पुल पर काम की स्थिति ऐसी है कि एक दिन मजदूर पहुंचते हैं और अगले दस दिन तक निर्माण स्थल पर सन्नाटा पसरा रहता है फिर जब कहीं से दबाव बनता है या खबर प्रकाशित होती है तो दोबारा थोड़ी गतिविधि दिखाई देती है, इस तरह काम करते-करते दो महीने से अधिक समय निकल चुका है और रपटा अब भी अधूरा है।

11 महीने में नहीं बन पाया वैकल्पिक पुल,तो स्थायी पुल कब बनेगा?

यही वह सवाल है जो आज हर ग्रामीण पूछ रहा है, एक वैकल्पिक रपटा पुल, जिसकी लागत केवल 15 लाख रुपये है और जिसका उद्देश्य केवल लोगों का आवागमन बहाल करना है, यदि 11 महीने में तैयार नहीं हो पाया तो करोड़ों रुपये की लागत वाला स्थायी पुल आखिर कब बना शुरू होगा? लोगों का कहना है कि यदि अस्थायी समाधान में ही इतना समय लग रहा है तो स्थायी समाधान के लिए शायद वर्षों इंतजार करना पड़े, स्थिति यह है कि स्थायी पुल का सपना भविष्य में है और वर्तमान का सहारा बनने वाला रपटा अभी तक अधूरा पड़ा है।

एसडीओ के निरीक्षण भी सवालों के घेरे में...

ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं,जहां करोड़ों रुपये वाला पुल बन रहा है वहां अधिकारी स्वयं पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन रपटा पुल के मामले में केवल पत्राचार और स्पष्टीकरण तक सीमित कार्रवाई दिखाई दे रही है, सूत्रों के अनुसार विभाग द्वारा नए इंजीनियर को जिम्मेदारी सौंपे जाने और ठेकेदार को पत्र जारी करने जैसी औपचारिकताएं की गई हैं,लेकिन ग्रामीण पूछ रहे हैं कि यदि पत्रों से पुल बनते तो देश में निर्माण कार्यों की कोई समस्या ही नहीं होती।

क्या टूटे-फूटे ह्यूम पाइप से बनेगा रपटा?

रपटा पुल निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, स्थानीय लोगों का दावा है कि निर्माण स्थल पर जो ह्यूम पाइप लाए गए हैं,वे नए नहीं लगते, कई पाइप टूटे-फूटे और पहले से उपयोग किए हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि किसी अन्य निर्माण स्थल पर उपयोग किए गए या बच गए पाइपों को यहां लाकर लगाया जा रहा है ताकि लागत कम की जा सके, यदि यह आरोप सही हैं तो यह केवल निर्माण गुणवत्ता का नहीं बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग का भी गंभीर मामला है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पहली तेज बारिश में यह रपटा बह गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

ग्रामीणों की जिंदगी बन गई रोज की परीक्षा

गोबरी नदी का पुल केवल एक संरचना नहीं था बल्कि दो जिलों के बीच जीवनरेखा था,इसके टूटने के बाद लोग लंबा और महंगा रास्ता अपनाने को मजबूर हैं, जो दूरी पहले कुछ मिनटों में तय हो जाती थी, उसके लिए अब 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है, छात्रों को स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है, किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में समय लग रहा है, कई ग्रामीण बताते हैं कि सुबह घर से निकलने वाला व्यक्ति शाम तक रास्ते की समस्या से जूझता रहता है।

शिवपुर मार्ग भी बना खतरे का रास्ता

समस्या केवल टूटे पुल तक सीमित नहीं है, नए पुल निर्माण के दौरान जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है, उसकी स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है, ग्रामीणों का आरोप है कि वहां पर्याप्त गिट्टी और मुरुम नहीं डाली गई है, परिणामस्वरूप दोपहिया वाहन चालक लगातार फिसल रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, बरसात शुरू होने के बाद इस मार्ग की स्थिति और खराब होने की आशंका है।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी चर्चा में...

जब पुल टूटा था तब कई जनप्रतिनिधियों ने मौके का दौरा किया था, तस्वीरें खिंची थीं,बयान दिए गए थे और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया गया था,लेकिन समय बीतने के साथ यह मुद्दा भी राजनीतिक प्राथमिकताओं की सूची से नीचे खिसकता गया,ग्रामीणों का कहना है कि अब कोई जनप्रतिनिधि इस विषय पर खुलकर बात नहीं करता,न कोई समय सीमा बताई जा रही है और न ही कोई जवाबदेही तय हो रही है।

जश्ने-जुबां में साहित्यकार बने सीईओ,झुमका में देश की आन-बान-शान पूछती रही...मुझे देखने कब आओगे साहब?

मैकल की अनुगूंज या जिम्मेदारियों की गूंज? झुमका का तिरंगा मांग रहा जवाब...
साहब! एक नजर इधर भी... जश्ने-जुबां में डूबे प्रशासन को झुमका के तिरंगे ने आईना दिखाया
मैकल की अनुगूंज में खोए साहब,तिरंगे ने लिख दी प्रशासन की असली कहानी
साहित्य के मंच पर सम्मान,झुमका में तिरंगे का अपमान
जश्ने-जुबां में व्यस्त साहब,झुमका में फटा तिरंगा करता रहा इंतजार
उपन्यास लिखते रहे अधिकारी,तिरंगा सुनाता रहा बदहाली की कहानी
विकास के दावों की पोल खोल गया झुमका का फटा तिरंगा...
मंच पर तालियां बटोरते रहे साहब,देश की शान होती रही तार-तार...
झुमका में तिरंगा बदहाल, जिम्मेदारों को दिखा सिर्फ अपना कमाल...
खुद की किताब अमेजन पहुंची, मगर तिरंगे तक न पहुंच सकी जिम्मेदारी
जश्न साहित्य का चलता रहा,झुमका में राष्ट्र सम्मान सिसकता रहा
फटा तिरंगा पूछ रहा सवाल, विकास हुआ या सिर्फ हुआ बवाल?
साहब लिखते रहे विकास की कहानी, तिरंगा दिखाता रहा जमीनी सच्चाई

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में इन दिनों एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है, एक तरफ जिला पंचायत के मुखिया साहित्यिक मंचों पर सम्मानित हो रहे हैं,अपनी लेखनी की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं,आलोचकों को जवाब देने में तत्पर हैं और मैकल की अनुगूंज जैसी रचनाओं के माध्यम से संवेदनाओं का संसार रच रहे हैं, दूसरी ओर उसी जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल झुमका अपने भीतर छिपी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है, जहां करोड़ों रुपये के विकास कार्यों के बीच देश की आन-बान-शान तिरंगा उपेक्षा का शिकार होकर खड़ा दिखाई दे रहा है, यह कहानी केवल एक तिरंगे की नहीं है, यह उस प्रशासनिक मानसिकता की कहानी है जिसमें तस्वीरें चमकती हैं लेकिन व्यवस्था धुंधली हो जाती है,भाषण गूंजते हैं लेकिन जिम्मेदारियां मौन हो जाती हैं।

जब साहित्यकार जाग गया,लेकिन प्रशासक सो गया...

सरकारी सेवा में साहित्य प्रेम होना बुरी बात नहीं है,एक अधिकारी का संवेदनशील होना भी स्वागत योग्य है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब साहित्यिक संवेदनशीलता प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भारी पड़ने लगे,कोरिया जिले में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ जिला पंचायत के मुखिया ने अपने कार्यकाल में साहित्यिक पहचान भी अर्जित की,पुस्तकें लिखीं, मंचों पर सम्मान पाए और एक लेखक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि जिस व्यक्ति की नजर शब्दों के दर्द को पहचान सकती है, वह झुमका में खड़े तिरंगे का दर्द क्यों नहीं देख पाया? क्या साहित्य केवल किताबों के पन्नों तक सीमित रह गया है? क्या संवेदनशीलता केवल मंचों पर तालियां बटोरने तक सीमित हो गई है?

अब निर्णय प्रशासन को करना है...

जनता ने अपनी बात कह दी है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, सवाल उठ चुके हैं, अब जिम्मेदारों के सामने दो रास्ते हैं,पहला रास्ता वही पुराना है सफाई देना, बयान जारी करना और आलोचकों को दोषी ठहराना,दूसरा रास्ता है की झुमका की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना, तिरंगे को सम्मानजनक स्थिति में लाना,निर्माण कार्यों की समीक्षा कराना और जनता को बताना कि आखिर करोड़ों रुपये का उपयोग किस तरह हुआ, यदि प्रशासन दूसरा रास्ता चुनता है तो विश्वास बचेगा,यदि पहला रास्ता चुना गया तो तिरंगा आने वाले दिनों में भी यही याद दिलाता रहेगा कि विकास के दावे चाहे जितने ऊंचे हों, उनकी असली परीक्षा जमीन पर होती है, और फिलहाल झुमका में खड़ा तिरंगा यही कहता दिखाई देता है कि मैकल की अनुगूंज लिखने से पहले प्रशासन को अपने कर्तव्यों की अनुगूंज भी सुननी चाहिए,क्योंकि राष्ट्रध्वज की खामोशी कभी-कभी सबसे बड़ा आरोप बन जाती है।

झुमका-विकास का मॉडल या प्रयोगशाला?

झुमका पर्यटन क्षेत्र कोरिया जिले की पहचान माना जाता है,इसे विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारी राशि खर्च की गई, ओपन थियेटर बना, सौंदर्यीकरण हुआ, पार्किंग बनाई गई और कई निर्माण कार्य कराए गए,कागजों में यह सब देखकर लगता है कि मानो झुमका किसी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल में बदल गया हो,लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है,ओपन थियेटर बनने के बाद उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे, उद्घाटन के कुछ समय बाद ही उसमें सुधार और मरम्मत की जरूरत महसूस होने लगी, पार्किंग व्यवस्था विवादों में घिर गई,स्थानीय लोगों और संचालकों की नाराजगी सामने आई। कई बार ऐसा लगा जैसे विकास कार्य जनता की सुविधा से ज्यादा फोटो सेशन के लिए किए गए हों, यदि कोई निष्पक्ष पर्यवेक्षक इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करे तो संभव है कि वह पूछ बैठे–यह विकास है या विकास का ट्रायल वर्जन?

तिरंगा पूछ रहा है...क्या मैं सिर्फ उद्घाटन के दिन के लिए था?

झुमका में स्थापित विशाल तिरंगा कभी गौरव का प्रतीक माना गया था, यह उस भावना का प्रतीक था जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया,लेकिन आज वही तिरंगा अपनी दुर्दशा के कारण चर्चा का विषय बन गया, विडंबना देखिए कि जिस प्रशासन के पास साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होने का समय है,सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने का समय है,सम्मान समारोहों में उपस्थित रहने का समय है,उसके पास अपने ही पर्यटन स्थल में लगे राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति देखने का समय नहीं है,तिरंगा यदि बोल सकता तो शायद यही कहता है साहब, आपने ओपन थियेटर देख लिया,मंच देख लिया,सम्मान देख लिया, किताब देख ली... कभी मुझे भी देख लेते।

खनिज न्यास निधि,विकास की गंगा या सुविधाओं की निजी नहर?

कोरिया जिले में लंबे समय से खनिज न्यास निधि को लेकर सवाल उठते रहे हैं, यह निधि मूल रूप से खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई थी ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि इस निधि का उपयोग कई बार ऐसे कार्यों में हुआ जिनकी प्राथमिकता जनता की जरूरतों से अधिक दिखावे से जुड़ी दिखाई दी, यदि इन कार्यों की गहन जांच हो तो संभव है कि कई ऐसे तथ्य सामने आएं जो विकास की चमकदार तस्वीरों के पीछे छिपे सच को उजागर कर दें,जनता का सवाल सीधा है–यदि करोड़ों रुपये खर्च हुए तो उनके परिणाम स्थायी क्यों नहीं दिखते?

आलोचना से असहज प्रशासन

लोकतंत्र में आलोचना कोई अपराध नहीं होती, बल्कि यह व्यवस्था को बेहतर बनाने का माध्यम होती है, लेकिन जिले में कई बार यह देखने को मिला कि आलोचनाओं का जवाब कार्यों से देने के बजाय भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से दिया गया,सोशल मीडिया पर चेतावनी जैसी भाषा का उपयोग भी चर्चा का विषय बना, सवाल यह है कि यदि सब कुछ सही है तो आलोचना से डर कैसा? एक मजबूत प्रशासक आलोचना का जवाब तथ्यों से देता है, कमजोर प्रशासक आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझ बैठता है।

तीन साल का कार्यकाल और बढ़ते सवाल

जिले में अब यह चर्चा भी आम होती जा रही है कि आखिर तीन वर्षों से अधिक के कार्यकाल में वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं? यदि उपलब्धियां हैं तो जनता उनमें गर्व क्यों महसूस नहीं कर रही? यदि विकास हुआ है तो उसका असर गांवों और आम लोगों के जीवन में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखाई देता? यदि पर्यटन क्षेत्र विकसित हुए हैं तो वहां बार-बार गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर शिकायतें क्यों सामने आती हैं? इन सवालों का जवाब किसी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी समीक्षा में छिपा है।

जश्ने-जुबां में तालियां,झुमका में खामोशी

हाल ही में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रमों में प्रशासनिक मुखिया की सक्रियता चर्चा का विषय रही, सम्मान, मंच और साहित्यिक संवादों के बीच उनकी उपस्थिति ने उन्हें एक लेखक के रूप में स्थापित किया,लेकिन उसी दौरान झुमका में खड़ा तिरंगा शायद किसी और ही कार्यक्रम का हिस्सा था–उपेक्षा महोत्सव का, एक तरफ तालियां बज रही थीं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक चुपचाप मौसम की मार झेल रहा था,यह दृश्य प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

जनता पूछ रही है...विकास का चेहरा कौन सा है?

जनता अब सरकारी विज्ञापनों और वास्तविकताओं की तुलना करने लगी है,एक तस्वीर में चमकदार परियोजनाएं दिखाई देती हैं, दूसरी तस्वीर में मरम्मत मांगते निर्माण कार्य,विवादों में घिरी व्यवस्थाएं और उपेक्षित तिरंगा दिखाई देता है, इन दोनों तस्वीरों में से असली तस्वीर कौन सी है? यही सवाल अब जिले की जनता पूछ रही है।

तिरंगे ने खोल दी विकास की फाइल

कई बार वर्षों की बहस और सैकड़ों शिकायतें भी वह प्रभाव नहीं छोड़ पातीं जो एक दृश्य छोड़ देता है, झुमका में तिरंगे की बदहाली ऐसा ही दृश्य बन गई है, इसने उन सभी सवालों को फिर से जीवित कर दिया है जिन्हें समय-समय पर दबाने की कोशिश की गई,यह केवल झंडे की कहानी नहीं है,यह रखरखाव की कहानी है, यह जवाबदेही की कहानी है। यह प्राथमिकताओं की कहानी है।

मनेन्द्रगढ़ कप-2026 का रोमांचक समापन,भगत सिंह वार्ड क्रमांक 17 बना चैम्पियन

फाइनल मुकाबले में वार्ड क्रमांक 22 को 55 रनों से हराया,हजारों खेलप्रेमियों की मौजूदगी में हुआ भव्य समापन समारोह

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़,01 जून 2026 (घटती-घटना)।

शहर के मिनी स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहे बहुप्रतीक्षित मनेन्द्रगढ़ कप-2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का शनिवार को शानदार और यादगार समापन हुआ, फ्लड लाइट की रोशनी में खेले गए फाइनल मुकाबले में भगत सिंह वार्ड क्रमांक 17 की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वार्ड क्रमांक 22 को 55 रनों से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया, टीम की जीत के साथ ही समर्थकों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला तथा मिनी स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा।

फाइनल मुकाबले में वार्ड 17 का दबदबा

लगातार सोलह वर्षों से आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट के सोलहवें संस्करण के फाइनल मुकाबले में वार्ड क्रमांक 17 और वार्ड क्रमांक 22 आमने-सामने थे, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वार्ड क्रमांक 17 की टीम ने शुरू से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया, टीम के ओपनर अभिषेक और संजय ने मजबूत शुरुआत दिलाई, विशेष रूप से संजय ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली, उनकी पारी की बदौलत वार्ड क्रमांक 17 ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए, वार्ड क्रमांक 22 की ओर से अंगद,मेहताब, सुमित, मनीष और फैज ने एक-एक विकेट हासिल किया।

हजारों खेल प्रेमियों की मौजूदगी ने बनाया यादगार आयोजन

फाइनल मुकाबले और समापन समारोह में हजारों की संख्या में खेल प्रेमियों की उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया, पूरे टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों का उत्साह और खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण रहा कि मनेन्द्रगढ़ कप अब केवल एक क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल उत्सव बन चुका है, यह रिपोर्ट समाचार पत्र, पोर्टल या स्मारिका प्रकाशन के लिए तैयार प्रारूप में है।

135 रनों के लक्ष्य के सामने लड़खड़ाई वार्ड 22 की टीम

136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वार्ड क्रमांक 22 की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी, हालांकि श्रेयस ने 30 रन और सुमित ने 20 रन बनाकर संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सके, पूरी टीम 80 रन पर सिमट गई और वार्ड क्रमांक 17 ने 55 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए मनेन्द्रगढ़ कप-2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली,वार्ड क्रमांक 17 की ओर से संजय ने गेंदबाजी में भी दो विकेट हासिल किए, जबकि अभिषेक ने तीन विकेट लेकर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,इसके अलावा सागर ने दो तथा शिवम और निखिल ने एक-एक विकेट प्राप्त किया।

संजय बने मैन ऑफ द मैच,अभिषेक को मिला मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार

फाइनल मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले संजय को मैन ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने 78 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के साथ दो विकेट भी हासिल किए, पूरे टूर्नामेंट में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर वार्ड क्रमांक 17 के खिलाड़ी अभिषेक बढेरा को मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया,अन्य व्यक्तिगत पुरस्कारों में बेस्ट बैट्समैन श्रेयस सिन्हा, बेस्ट बॉलर विक्की, बेस्ट फील्डर गगन को प्रदान किए गए।

भव्य समापन समारोह में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री

टूर्नामेंट के समापन समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए,कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि,समाजसेवी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे, अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रेसीडेंट क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ युवाओं में अनुशासन,खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास कर रही है,उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मिनी स्टेडियम के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं

समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मनेन्द्रगढ़ के मिनी स्टेडियम में खेल सुविधाओं के विस्तार की घोषणा करते हुए बताया कि दर्शकों के लिए अतिरिक्त सिटिंग व्यवस्था विकसित करने हेतु 98 लाख रुपये के कार्य का टेंडर जारी किया जा चुका है तथा जल्द ही इसका भूमिपूजन किया जाएगा, इसके अलावा उन्होंने मिनी स्टेडियम में बेहतर रात्रिकालीन खेल व्यवस्था के लिए 24 लाख रुपये की अतिरिक्त फ्लड लाइट लगाने की घोषणा भी की, मंत्री की इन घोषणाओं का खेल प्रेमियों ने तालियों के साथ स्वागत किया।

आयोजन समिति को मिला सम्मान

कार्यक्रम के दौरान सफल आयोजन के लिए प्रेसीडेंट क्लब के अध्यक्ष अधिवक्ता आशीष सिंह को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया,उन्होंने सभी खिलाड़ियों, दर्शकों, प्रायोजकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष सभी 22 वार्डों के खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है,उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में यह प्रतियोगिता और अधिक भव्य स्वरूप में आयोजित होगी तथा यहां से निकलने वाले खिलाड़ी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मनेन्द्रगढ़ का नाम रोशन करेंगे।

C M Y K

जून का महीना होगा मनोरंजन से भरपूर

थिएटर्स में रोमांस,ड्रामा और एक्शन का तड़का लगाएंगी ये 8 फिल्में

सिनेमा लवर्स के लिए जून 2026 मनोरंजन से भरपूर होगा क्योंकि इस महीने में कॉमेडी से लेकर ड्रामा तक और एक्शन से लेकर रोमांस तक का तड़का लगने वाला है। मूवी लवर्स के लिए जून का महीना शानदार होने वाला है क्योंकि इस महीने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं। थिएटर्स में एक तरफ जहां वेलकम टू जंगल सबको हंसाएगी वहीं कॉकटेल 2 प्यार का तड़का लगाएगी। पूरे जून में कब-कौन सी फिल्म दस्तक देने जा रही है।

है जवानी तो इश्क होना है

इस साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली कमर्शियल एंटरटेनर फिल्मों में से एक, है जवानी तो इश्क़ होना है में वरुण धवन अपने डायरेक्टर-पिता डेविड धवन के साथ फिर से नजर आएंगे। पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ इस फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और क्लासिक बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का पूरा मसाला होने की उम्मीद है। यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

बंदर

निर्देशक अनुराग कश्यप बंदर के साथ वापसी कर रहे हैं। यह एक ड्रामा फिल्म है जिसमें बॉबी देओल , सान्या मल्होत्रा, सबा आजाद और अन्य कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एक संघर्षरत कलाकार की कहानी है, जिसकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आता है, जब वह एक ऐसे विवाद में फंस जाता है जो उसे पूरी तरह से तबाह करने की धमकी देता है। यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

मैं वापस आऊंगा

अमर सिंह चमकीला की सफलता के बाद, इम्तियाज अली एक दिल को छू लेने वाले ड्रामा के साथ वापसी कर रहे हैं, जिसमें दिलजीत दोसांझ , शरवरी, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं। बताया जा रहा है कि यह कहानी पीढ़ियों के बीच प्यार, यादों और रिश्तों को दर्शाती है। यह फिल्म 12 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी।

हॉन्टेड 3डी

सुपरनैचुरल हॉरर के फैन्स हॉन्टेड फ्रैंचाइजी की नई किस्त का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव, पैरानॉर्मल रहस्य और फ्रैंचाईजी के जाने-पहचाने हॉरर स्टाइल की वापसी का वादा करती है। यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

गवर्नर

मनोज बाजपेयी और अदा शर्मा अभिनीत, इस थ्रिलर फिल्म से एक ऐसी दिलचस्प कहानी की उम्मीद है जो सस्पेंस और राजनीतिक दांव-पेच से भरपूर होगी। इस फिल्म का निर्देशन चिन्मय डी. मांडलेकर ने किया है। यह मूवी 12 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी।

भारत भाग्य विधाता

भारत भाग्य विधाता एक आने वाली देशभक्ति थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका में हैं। मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित और समर्थित, यह फिल्म 2008 के आतंकी हमलों के दौरान मुंबई के कामा अस्पताल के स्टाफ की सच्ची और अक्सर अनकही कहानी पर आधारित है। यह फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार समेत लगभग 40 कलाकारों की टुकड़ी के साथ आ रही मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल भी थिएटर्स में दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पटानी जैसे सितारों की एक बड़ी टोली नज़र आएगी। कॉमेडी, एक्शन और जबरदस्त हलचल से भरपूर, इस फिल्म के इस महीने की सबसे बड़ी रिलीज में से एक होने की उम्मीद है। यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कॉकटेल 2

2012 की हिट फिल्म कॉकटेल की अगली कड़ी, कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर , कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक ग्लैमरस बैकग्राउंड में दोस्ती, रोमांस और उलझे हुए रिश्तों को दिखाती है। यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

फ्लॉप फिल्मों से डूबा करियर,फिर शानदार वापसी कर छाए बॉबी देओल और अक्षय खन्ना

बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही अनिश्चितताओं से भी भरी हुई है। यहां एक फिल्म किसी कलाकार को रातोंरात स्टार बना सकती है, तो लगातार कुछ फ्लॉप फिल्में उसके करियर को मुश्किल दौर में पहुंचा सकती हैं। 90 के दशक में भी दो ऐसे सितारे बॉलीवुड में आए, जिन्होंने अपने डेब्यू के साथ ही जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की, लेकिन बाद में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। ये सितारे हैं बॉबी देओल और अक्षय खन्ना। दोनों अभिनेताओं ने 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और शुरुआत में दर्शकों का खूब प्यार हासिल किया। बॉबी देओल ने अपनी पहली फिल्म बरसात से धमाकेदार शुरुआत की थी। उनकी मासूमियत, स्टाइल और अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया। वहीं अक्षय खन्ना ने हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में एंट्री की और बाद में कई फिल्मों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। शुरुआती सफलता के बाद दोनों कलाकारों का करियर धीरे-धीरे मुश्किल दौर में पहुंच गया। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं। लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण निर्माताओं और निर्देशकों का भरोसा भी कम होने लगा। हालात ऐसे हो गए कि दोनों सितारों को लंबे समय तक बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिले और वे फिल्मों से लगभग दूर हो गए। बॉबी देओल के लिए यह दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लंबे समय तक काम नहीं मिला। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को नए सिरे से तैयार किया। उनकी किस्मत तब बदली जब वे वेब सीरीज और अलग तरह के किरदारों में नजर आए। इसके बाद फिल्म एनीमल में उनके किरदार ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। कम स्क्रीन टाइम के बावजूद उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई और वे फिर से चर्चा में आ गए। दूसरी ओर अक्षय खन्ना ने भी अपने अभिनय के दम पर वापसी की। वे हमेशा से अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते रहे हैं। कुछ समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद उन्होंने दमदार भूमिकाओं के साथ वापसी की और यह साबित कर दिया कि प्रतिभा कभी खत्म नहीं होती। फिल्मों में उनके गंभीर और प्रभावशाली किरदारों को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। दोनों कलाकारों की कहानी इस बात का उदाहरण है कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता और असफलता स्थायी नहीं होती। कठिन दौर के बाद भी अगर कलाकार अपने हुनर और मेहनत पर भरोसा बनाए रखे, तो वापसी संभव है। आज बॉबी देओल और अक्षय खन्ना एक बार फिर इंडस्ट्री में सम्मानजनक स्थान रखते हैं। उनकी यात्रा नए कलाकारों के लिए भी प्रेरणा है कि असफलताओं से घबराने के बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है।

कटरीना को छोड़ दिशा संग अक्षय ने लगाए ठुमके

ऊंचा लंबा कद का नया वर्जन रिलीज

अक्षय कुमार और दिशा पाटनी अभिनीत फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना ऊंचा लंबा कद फॉरएवर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म वेलकम टू द जंगल से धमाल मचाने आ रहे हैं। वेलकम सीरीज के इस थर्ड पार्ट में इस बार कहानी अलग होगी और मजेदार होगी, तो वहीं फिल्म वेलकम वन के कल्ट सॉन्ग को इस फिल्म में रीक्रिएट किया गया है और गाने का नाम है ऊंचा लंबा कद, जो हाल ही में रिलीज कर दिया गया है।

ऊंचा लंबा कद गाना हुआ रिलीज

फिल्म वेलकम टू द जंगल पहले से ही जमकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के गाने और टीजर्स को काफी पसंद किया गया है और अब फिल्म का नया गाना ऊंचा लंबा कद फॉरएवर रिलीज कर दिया गया है। अक्षय कुमार के साथ इस गाने में इस बार कटरीना कैफ नहीं बल्कि दिशा पाटनी नजर आईं हैं। ओरिजनल गाने का संगीत आनंद राज आनंद ने तैयार किया था, जबकि इसके नए वर्जन को विक्रम मॉन्ट्रोज ने रीक्रिएट किया है। हालांकि गाना सुनने के बाद वैसा फील कतई नहीं दे रहा है, जो ओरिजिनल वर्जन में था। हां, पर इतना जरूर है कि मेकर्स ने इसमें बहुत ज्याद छेड़छाड़ नहीं की है।

गाने में छाई दिशा-अक्षय की केमिस्ट्री

इस गाने में अक्षय के साथ इस बार फैंस कटरीना कैफ को तो मिस कर ही रहे हैं, लेकिन हां दिशा ने अपनी बोल्ड अदाओं से जादू चलाने की कोशिश जरूर की है। दिशा का अलग अंदाज इसे थोड़ा पार्टी वाला फील दे रहा है। गाने के इस नए वर्जन को आनंद राज आनंद और रुबाई ने अपनी आवाज दी है।

इसके अलावा मेघा बाली ने गाने में कुछ नए लिरिक्स को जोड़ा है। गाने की बीट्स कमाल की हैं और वहीं लोकेशन्स की बात करें तो इससे पहले अक्षय के कई गानों में ऐसा अंदाज नजर आ चुका है। पार्टी एंथम बनकर आया ये गाना फिलहाल तो रिलीज हो चुका है और अब दर्शक इसे कितना पसंद करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको बता दें कि वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, ज़ाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडेय, बृजेंद्र काला, फिरोज खान (अर्जुन), दिवंगत अभिनेता पंकज धीर, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्या सिंह और भाग्य भानुशाली जैसे स्टार्स इसमें नजर आएंगे।अहमद खान के डायरेक्शन में बनी वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

तृषा कृष्णन की 5 पारिवारिक फिल्में: रोमांस से आगे भी दिखा दमदार अभिनय

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री तृषा कृष्णन ने अपने लंबे करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं। रोमांटिक फिल्मों से लेकर एक्शन और फैमिली ड्रामा तक, उन्होंने हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि, कई लोग उन्हें सिर्फ रोमांटिक फिल्मों तक सीमित मानते हैं, लेकिन सच यह है कि तृषा ने कई बेहतरीन पारिवारिक फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। अपने करियर में तृषा ने यह साबित किया है कि वह सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक कहानियों में भी उतनी ही सहजता से अभिनय कर सकती हैं। उनकी कई फिल्मों में परिवार, रिश्तों और भावनाओं की गहराई को खूबसूरती से दिखाया गया है।

1. **'सिंघम 2'** इस फिल्म में तृषा ने एक मजबूत महिला किरदार निभाया था। फिल्म में परिवार और समाज के बीच संतुलन की कहानी को दिखाया गया है। एक्शन के साथ-साथ इसमें पारिवारिक भावनाओं का भी अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है।
2. **'सामि 2'** इस फिल्म में तृषा एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आईं। कहानी में परिवार और कर्तव्य के बीच संघर्ष को दिखाया गया है, जिसमें उनके किरदार ने भावनात्मक गहराई जोड़ी।

खेल समाचार

रेड बॉल टेस्ट के बीच में भी होगा पिंक बॉल का इस्तेमाल

आईसीसी ने रेड बॉल टेस्ट मैच में खराब मौसम होने पर पिंक बॉल के ट्रायल को मंजूरी दे दी है...ट्रायल बेसिस पर इसका इस्तेमाल होगा...इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल मैचों में ब्रेक 15 मिनट का होगा...

अहमदाबाद,01 जून 2026। आईसीसी ने सभी टेस्ट मुकाबलों में पिंक बॉल के इस्तेमाल के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब मौसम खराब होने का खतरा हो, तो खराब रोशनी के कारण खेल पर कोई असर न पड़े। खेल लाइट्स में भी जारी रह सके। मैच अधिकारियों और स्टेडियम के लिए लाइटिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी की जाएगी, ताकि खराब रोशनी के कारण खेल में होने वाली रुकावटों को कम किया जा सके। इस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आईसीसी, %मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब% (एमसीसी) के साथ मिलकर आर्थिक मदद देगा। इस बैठक में मैच अधिकारियों को अवैध बॉलिंग एक्शन पर फैसला लेते समय हॉक-आई डेटा का इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है।

टी20 इंटरनेशनल में 15 मिनट का ब्रेक

आईसीसी बोर्ड की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि हेड कोच या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि, तय ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान टीमों से सलाह-मशविरा कर सकेंगे। इसके अलावा, टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 15 मिनट का ब्रेक अनिवार्य कर दिया गया है। ब्लेबाजों के लिए खेल दोबारा शुरू होते ही खेलने के लिए तैयार रहना अनिवार्य होगा। आईसीसी बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी की कई सिफारिशों को मंजूरी दी है। इनमें टेस्ट मुकाबलों में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का ट्रायल शामिल है, जिसके लिए दोनों टीमों की पहले से सहमति जरूरी होगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर खराब रोशनी की आशंका हो, तो भी खेल को अधिक से अधिक समय तक जारी रखा जा सके।

आईसीसी ने लेगसाइड वाइड के ट्रायल को स्थायी रूप से लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एमसीसी के क्रिकेट के नियमों में किए गए शेष सभी बदलाव भी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। आधिकारिक क्रिकेट के वर्गीकरण में भी कुछ बदलावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत, यह पुष्टि की गई है कि सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग में हिस्सा लेने वाली टीमें, चैलेंज लीग के प्रत्येक टूर्नामेंट चक्र के दौरान लिस्ट-ए श्रेणी के अन्य सीमित ओवरों वाले मैच खेलने के लिए भी पात्र बनी रहेंगी।

आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा को मेंबरशिप से सस्पेंड किया

नई दिल्ली,01 जून 2026। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट कनाडा को उसके मेंबरशिप नियमों के गंभीर उल्लंघन के बाद तुरंत सस्पेंड कर दिया है। आईसीसी ने यह कदम उठाया है क्योंकि नेशनल गवर्निंग बॉडी ने अपनी मेंबरशिप की शर्तों का पालन नहीं किया, जिससे क्रिकेट के प्रशासन और विकास पर सवाल उठ गए हैं। आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि कनाडा की नेशनल टीम और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अब केवल आईसीसी की निगरानी और नियंत्रित फंडिंग सिस्टम के तहत ही फंडिंग प्राप्त कर पाएंगे। आईसीसीके बयान में कहा गया, आईसीसी बोर्ड ने क्रिकेट कनाडा को तुरंत सस्पेंड करने का फैसला किया है। यह निर्णय तब लिया गया जब यह स्पष्ट हुआ कि क्रिकेट कनाडा ने अपनी मेंबरशिप की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया है। नेशनल टीमों की लगातार भागीदारी और क्रिकेट के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, क्रिकेट कनाडा को अब आईसीसीमैनेजमेंट के अधीन, केवल मंजूर नेशनल टीम प्रोग्राम के लिए फंडिंग मिलेगी। आईसीसी ने यह भी कहा कि सस्पेंशन का उद्देश्य क्रिकेट कनाडा में प्रशासनिक सुधार लाना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। आईसीसी का मानना है कि सही प्रशासन और पारदर्शी प्रबंधन के बिना क्रिकेट कनाडा की भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। नियंत्रित फंडिंग सिस्टम के जरिए आईसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि फंडिंग सीधे नेशनल टीम और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तक पहुंचे और भ्रष्टाचार या अनुचित खर्च से बचा जा सके।

आरसीबी का लगातार दूसरी आईपीएल जीत के बाद परेड नहीं करने का फैसला

अहमदाबाद,01 जून 2026। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी इंडियन प्रीमियर लीग खिताबी जीत के बाद इस बार शहर में विक्ट्री परेड न करने का फैसला किया है। फ्रेंचाइजी ने यह कदम भीड़ से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं और पिछले अनुभवों को देखते हुए उठाया है। जानकारी के अनुसार,आरसीबी ने यह निर्णय किसी संभावित भीड़भाड़ और गुस्से की स्थिति से बचने के लिए लिया है। इससे पहले 4 जून 2025 को पहली खिताबी जीत के बाद आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसने पूरे क्रिकेट और फैन कम्युनिटी को झकझोर दिया था। इसी दर्दनाक घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार फ्रेंचाइजी ने किसी भी तरह के बड़े सार्वजनिक जश्न या परेड से दूरी बनाने का फैसला किया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण जी एंटरटेनमेंट के पास

नई दिल्ली,01 जून 2026।फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप2026 को लेकर भारत में बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछले कई दिनों से इस मेगा इवेंट के प्रसारण अधिकारों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी था। भारतीय फुटबॉल प्रेमी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर विश्व कप के मुकाबले किस प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकेंगे। अब इस सस्पेंस पर विराम लग गया है और फुटबॉल फैंस के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लाइव टेलीकास्ट और प्रसारण अधिकार इंटरटेनमेंट इंटरप्राईजेज ने हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही देशभर के करोड़ों दर्शक विश्व कप के रोमांचक मुकाबलों का आनंद जी नेटवर्क के माध्यम से ले सकेंगे। बीते कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि टूर्नामेंट के प्रसारण को लेकर विभिन्न मीडिया कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है। चर्चा थी कि कुछ बड़े डिजिटल और प्रसारण प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत अंतिम चरण तक पहुंची थी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया। अब अधिकार जी एंटरटेनमेंट के पास आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है।

स्वागत पीछे से,व्यवस्था नीचे से और गुस्सा ऊपर से,बेमेतरा में प्रशासन पर बरसे रमन सिंह

प्रोटोकॉल हुआ ध्वस्त तो मंच से गरजे रमन सिंह,कलेक्टर-एसपी को दी खुली चेतावनी

आंधी से उड़ा पंडाल,व्यवस्था से उड़ा भरोसा, बेमेतरा में फूटा विधानसभा अध्यक्ष का गुस्सा...

मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल पर सवाल,विधानसभा अध्यक्ष ने मंच से लगाई प्रशासन को फटकार...

'यह परंपरा नहीं,अक्षम्य भूल है'-बेमेतरा में अधिकारियों पर बरसे विधानसभा अध्यक्ष

बेमेतरा बना प्रशासनिक पाठशाला,विधानसभा अध्यक्ष ने मंच से पढ़ाया प्रोटोकॉल का पाठ

जब विधानसभा अध्यक्ष को मंच से याद दिलानी पड़ी मर्यादा,तब कटघरे में खड़ा हुआ प्रशासन

माननीयों का सम्मान भी नहीं संभाल पाया प्रशासन,बेमेतरा में खुल गई व्यवस्थाओं की पोल

पंद्रह साल के मुख्यमंत्री का छलका अनुभव, बोले...ऐसी व्यवस्था दोबारा नहीं दिखनी चाहिए

क्या बेलगाम हो चुका है प्रशासन? बेमेतरा में विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी ने खड़े किए बड़े सवाल...

फटकार या बड़ी सीख? बेमेतरा में भड़के विधानसभा अध्यक्ष,कलेक्टर-एसपी को मंच से सुनाई खरी-खरी

-न्यूज डेस्क-

रायपुर 01 जून 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अक्सर नेताओं की नाराजगी बंद कमरों तक सीमित रहती है, लेकिन बेमेतरा में जो दृश्य सामने आया उसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने खुले मंच से जिस तरह प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की, उसने यह संकेत दे दिया कि मामला केवल एक कार्यक्रम की अव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन और प्रशासन के बीच बढ़ती दूरी का सार्वजनिक प्रदर्शन बन चुका है, ढाई वर्ष के कार्यकाल में पहली बार ऐसा अवसर देखने को मिला जब विधानसभा अध्यक्ष को मंच से ही कलेक्टर और एसपी को नसीहत देनी पड़ी, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह केवल एक जिले की घटना नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के लिए चेतावनी का संदेश था।

आंधी आई तो उड़ गया पंडाल,साथ में उड़ गई प्रशासनिक तैयारी भी...

बेमेतरा में सुशासन तिहार,सामूहिक विवाह सम्मेलन और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन था,कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री,केंद्रीय राज्य मंत्री, मंत्रीगण और विधायक मौजूद थे, ऐसे आयोजन में सुरक्षा, प्रोटोकॉल और वैकल्पिक व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता मानी जाती है,लेकिन तेज आंधी और बारिश ने जैसे ही दस्तक दी,प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुल गई,टेंट और पंडाल धराशायी होने लगे,कुर्सियां उड़ने लगीं और व्यवस्था संभालने का दावा करने वाले अधिकारी एक-दूसरे की ओर देखने लगे, सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि वीवीआईपी स्तर के कार्यक्रम में वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल क्यों नहीं हो सकी? बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे तक अधिकारी इस बात पर ही सहमति नहीं बना पाए कि कार्यक्रम को किस स्थान पर शिफ्ट किया जाए, यही वह बिंदु था जिसने विधानसभा अध्यक्ष को सबसे ज्यादा नाराज किया।

प्रोटोकॉल पर पड़ा ग्रहण,स्वागत भी पीछे से!

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी केवल टेंट उड़ने तक सीमित नहीं थी,उन्हें इस बात ने अधिक विचलित किया कि मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीयों के स्वागत और प्रोटोकॉल का पालन भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हुआ,कहा जा रहा है कि कुछ माननीयों का स्वागत पीछे से किया गया, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के आगमन और स्वागत की स्पष्ट व्यवस्था होती है, मंच से विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह परंपरा नहीं है,यह उचित नहीं है और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं दिखनी चाहिए,उनकी भाषा भले संयमित थी, लेकिन संदेश बेहद कठोर था।

क्या प्रशासन मर्यादा भूल गया है?

सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रशासनिक अमला अब राजनीतिक और संवैधानिक पदों की गरिमा को लेकर उतना सजग नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था? डॉ. रमन सिंह कोई साधारण जनप्रतिनिधि नहीं हैं,वे पंद्रह वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर आसीन हैं, ऐसे में उनका सार्वजनिक रूप से नाराज होना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती,राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को मंच से अधिकारियों को याद दिलाना पड़े कि प्रोटोकॉल क्या होता है, तो यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है।

बेमेतरा से निकला संदेश पूरे प्रदेश के लिए?

घटना भले बेमेतरा की हो,लेकिन इसके संदेश को पूरे प्रदेश के संदर्भ में देखा जा रहा है, कई जनप्रतिनिधि लंबे समय से यह शिकायत करते रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संवाद में अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे,कई जिलों में विधायक और अधिकारी आमने-सामने तक आ चुके हैं,ऐसे माहौल में विधानसभा अध्यक्ष की यह टिप्पणी केवल तत्कालीन व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवहार में सुधार का सार्वजनिक निर्देश भी मानी जा रही है।

सरल मुख्यमंत्री और बेलगाम व्यवस्था?

भाजपा संगठन के भीतर भी लंबे समय से यह चर्चा सुनाई देती रही है कि मुख्यमंत्री की सहज और सौम्य कार्यशैली का लाभ कुछ अधिकारी अपनी सुविधानुसार उठा रहे हैं,कई कार्यकर्ता यह आरोप लगाते हैं कि प्रशासनिक तंत्र कई मामलों में जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से नहीं लेता। शिकायतें सुनने के बजाय फाइलों को इधर-उधर घुमाने की संस्कृति विकसित हो रही है,बेमेतरा की घटना ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है।

जब माननीयों का यह हाल है तो आम जनता का क्या?-इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वह है जिस पर आम जनता चर्चा कर रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में व्यवस्था इस स्तर तक बिगड़ सकती है,तो आम नागरिकों की समस्याओं को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता होगा? राजस्व विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन तक आम लोगों की शिकायतें पहले से ही लंबित मामलों, चक्कर काटने और कथित भ्रष्टाचार को लेकर सामने आती रही हैं,यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष की फटकार को कई लोग जनता की भावना का प्रतिबिंब भी मान रहे हैं।

फटकार नहीं,प्रशासनिक आईना था बेमेतरा का मंच

बेमेतरा का मंच केवल एक कार्यक्रम का मंच नहीं था,वह प्रशासनिक कार्यशैली का आईना बन गया, विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की,उससे यह स्पष्ट संकेत गया कि व्यवस्था केवल कागजों और प्रस्तुतियों से नहीं चलती। संकट की घड़ी में निर्णय क्षमता, समन्वय और जिम्मेदारी सबसे बड़ी कसौटी होती है, अब देखने वाली बात यह होगी कि बेमेतरा की यह सार्वजनिक सीख केवल तालियों तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव दिखाई देता है,क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने मंच से जो कहा,वह केवल कलेक्टर और एसपी के लिए नहीं था, वह पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए एक संदेश था पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो,प्रोटोकॉल, मर्यादा और जवाबदेही से बड़ा नहीं हो सकता।

सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था पर गरमाई राजनीति

रमन सिंह के वायरल वीडियो पर भूपेश बघेल और दीपक बैज ने कसा तंज

रायपुर,01 जून 2026। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हुई अव्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की सार्वजनिक नाराजगी अब राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए रमन सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ रही है और सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में डॉ. रमन सिंह का इस तरह नाराज होना सामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह का बयान एक राजनीतिक संदेश की तरह है। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि डॉ. रमन सिंह मानो यह कह रहे हों कि'तुमसे ना हो पाएगा' और अपनी

कुर्सी खाली कर दो। भूपेश बघेल ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अव्यवस्थाओं और शिकायतों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा,'सरकार के नियंत्रण में अब कुछ नहीं रहा है। ' प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष खुद व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हों, वहां सरकार के सुशासन के दावों की वास्तविकता सामने आ जाती है। बैज ने कहा कि अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का पीछे से स्वागत कर रहे थे और खुद रमन सिंह सार्वजनिक मंच से नाराजगी जाहिर कर रहे थे।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला...ईडी ने 1200 करोड़ की संपत्तियां अटैच की

गोवा का लग्जरी होटल भी जांच के घेरे में,कारोबारी भाटिया-निखिल,टी. भुनेश्वर राव-प्रबीर शर्मा भी आरोपी

रायपुर,01 जून 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने 28 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए। कुर्क संपत्तियों की डीड वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए जबकि बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है।

रायपुर में जमीनें, बेनामी संपत्तियां भी कुर्क : पहले कुर्की आदेश में विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। ईडी के मुताबिक विकास अग्रवाल सिंडिकेट के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता था और डिस्टिलरियों तथा स्तर10 लाइसेंसधारकों से कमीशन की रकम जुटाकर सिंडिकेट तक पहुंचाता था। कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित ढेबर सिटी होम्स के कई भूखंडों के अलावा विभिन्न शेल कंपनियों के नाम पर खरीदी गई जमीनों को भी कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए बताया गया है।

शराब घोटाले के पैसे से खरीदा गया गोवा का होटल : दूसरे कुर्की आदेश में उत्तर गोवा के अंजुना स्थित प्रीमियम होटल 'वेस्टइन गोवा' को अटैच किया गया है। होटल पैसिफिका होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। ईडी का दावा है कि करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई यह संपत्ति शराब घोटाले से प्राप्त बेहिसाबी नकदी से खरीदी गई थी। जांच में चैतन्य बघेल के निर्देश पर नकदी के परिवहन का भी उल्लेख किया गया है।

तीन कंपनियों के खाते और निवेश जब्त : तीसरे आदेश के तहत ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड अटैच किए गए हैं। ईडी का आरोप है कि इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा सिंडिकेट को देने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे करीब 51 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। ईडी ने रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में छठी पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। इसमें कारोबारी विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को आरोपी बनाया गया है।

सिंडिकेट का संचालन करते थे ढेबर-टुटेजा

ईडी के अनुसार,आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और एसीबी रायपुर की एफआईआर के आधार पर हुई जांच में सामने आया कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच एक संगठित शराब सिंडिकेट ने आबकारी व्यवस्था में हेरफेर कर 2883 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध आय अर्जित की। जांच एजेंसी का दावा है कि इस सिंडिकेट का संचालन अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के नेतृत्व में किया जा रहा था।

रायपुर में बिजली संकट...कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन,नए सब स्टेशन बनाने की मांग,पूर्व विधायक विकास बोले...अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे

रायपुर,01 जून 2026। बिजली कटौती,लो-वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्याओं को लेकर रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है और संबंधित विभाग समस्याओं के समाधान में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि,गुढ़ियारी क्षेत्र राजधानी का घनी आबादी वाला इलाका है,जहां बिजली संबंधी समस्याएं सबसे अधिक हैं। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यहां बिजली सब-स्टेशन के लिए फंड स्वीकृत किया गया था। लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना अधूरी पड़ी हुई है। उनका कहना है कि रायपुर में नजूल और ट्रस्ट की पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल बिजली विभाग को सब-स्टेशन निर्माण के लिए किया जा सकता है। उपाध्याय ने कलेक्टर को सुझाव देते हुए कहा कि,गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम या संजय गांधी नगर के आसपास उपलब्ध रिक्त भूमि पर तत्काल नया बिजली सब-स्टेशन स्थापित किया जाए,जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। रामनगर,गोकुल नगर,कृष्णा नगर,अशोक नगर,तिलक नगर, रायपुरा,डीडी नगर,सुंदर नगर,लाखे नगर, टकरापारा और पुरानी बस्ती सहित कई इलाकों के लोग बिजली संकट से परेशान हैं।

छत्तीसगढ़ में करणी-सेना के प्रदेश अध्यक्ष पद पर छिड़ा विवाद....

राज शेखावत बोले...अभिषेक कभी अधिकृत अध्यक्ष नहीं थे 220 पदाधिकारियों के संगठन छोड़ने का दावा फिजूल

रायपुर,01 जून 2026। छत्तीसगढ़ में राजपूत समाज की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों के केंद्र में बनी करणी सेना का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। कुछ दिन पहले डॉ. राज शेखावत की क्षत्रिय करणी सेना छोड़कर कालवी विचारधारा वाली राजपूत करणी सेना में शामिल हुए अभिषेक कुमार सिंह ने दावा किया था कि,उनके साथ प्रदेश के 220 पदाधिकारी भी संगठन छोड़ चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर अभिषेक सिंह के दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। शेखावत का कहना है कि अभिषेक सिंह कभी भी संगठन के विधिवत नियुक्त और अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। उन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का

दायित्व दिया गया था। संगठन के अनुसार छत्तीसगढ़ के अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष पहले भी वीरेंद्र सिंह तोमर थे और वर्तमान में भी वही प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि, अभिषेक सिंह और उनके कुछ सहयोगी संगठन के संविधान, अनुशासन और निर्धारित व्यवस्था के विपरीत गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसकी समीक्षा के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय लिया था। संगठन का दावा है कि कार्यकारिणी भंग होने के बाद संबंधित लोगों के पास संगठन का प्रतिनिधित्व करने या उसके नाम से बयान जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।

220 पदाधिकारियों के दावे पर उठाए सवाल : राष्ट्रीय कार्यालय ने अभिषेक सिंह के उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें उन्होंने अपने साथ 220 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के संगठन छोड़ने की बात कही थी। संगठन का कहना है कि अभिषेक सिंह के पास न तो संगठन की वास्तविक सदस्य संख्या का अधिकृत रिकॉर्ड था और न ही वे ऐसी स्थिति में थे कि पूरे प्रदेश संगठन की ओर से कोई दावा कर सकें। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अधिकांश जिला, तहसील, संभाग और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी आज भी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन की विचारधारा के प्रति निष्ठावान हैं।

तोमर बंधुओं के मुद्दे के बाद बढ़े मतभेद : दरअसल, प्रदेश में चर्चित तोमर बंधुओं के मामले के दौरान क्षत्रिय करणी सेना की ओर से चलाए गए आंदोलन के बाद संगठन के भीतर वैचारिक मतभेद सामने आने लगे थे। उस समय प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन अभिषेक सिंह की टीम कर रही थी। आंदोलन के दौरान संगठन को विरोध और आलोचना का भी सामना करना पड़ा था।

देश में 147 आईपीएस पदों का अलॉटमेंट...रिटायरमेंट नहीं होने से छत्तीसगढ़ के हिस्से नहीं आया कोई पद, अगले साल भी कम पद मिलने की उम्मीद

रायपुर,01 जून 2026। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल सेवा परीक्षा-2024 के जरिए चयनित आईपीएस अधिकारियों के लिए विभिन्न राज्यों में कैडर आवंटन हेतु रिक्तियों की सूची जारी कर दी है। देशभर में कुल 147 आईपीएस पदों का वितरण किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के हिस्से एक भी पद नहीं आया है। अधिसूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक 15 आईएएस पद मिले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश को 14, उत्तर प्रदेश को 12, असम-मेघालय और मध्य प्रदेश को 11-11 तथा महाराष्ट्र को 10 पद आवंटित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए कोई पद अधिसूचित नहीं किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अगले एक साल तक किसी आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड नहीं होने वाली है। यही वजह है कि नए पद खाली नहीं हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्य ने केंद्र को कोई रिक्ति नहीं भेजी, इसलिए इस बार नए आईपीएस अधिकारियों के कैडर

आवंटन में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के कुल 153 स्वीकृत पद हैं। इनमें 31 पद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के लिए तय हैं। फिलहाल 11-12 आईपीएस अधिकारी केंद्र में डेपुटेशन पर हैं, जबकि बाकी अधिकारी राज्य में पदस्थ हैं। अधिकांश पद भरे होने की वजह से फिलहाल कोई नई रिक्ति नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अगर राज्य सरकार ने विशेष प्रयास कर नए पद नहीं बनवाए तो अगले साल भी छत्तीसगढ़ को नए आईपीएस अधिकारी नहीं मिल सकते। वर्ष 2027 में भी केवल एक आईपीएस अधिकारी के रिटायर होने की संभावना है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)